शर्मा हार्डওয়্যার
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 13 | अंक : 13 | गुवाहाटी | गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

सीएम डॉ. शर्मा ने गुवाहाटी बाढ़ के पीछे कई विफलताओं का जिक्र किया पेज 2
यूपीपीएल प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से बीटीआर समझौता क्रियान्वयन... पेज 3
योगी सरकार का भूमाफियाओं पर प्रहार, अवैध कब्जे से मुक्त कराई दो लाख... पेज 5
हर घर तिरंगा रैली में बोले खेल मंत्री, फिटनेस के साथ प्रदूषण और ट्रैफिक... पेज 7

जेपीसी को भेजा गया एफसीआरए विधेयक

नई दिल्ली (हि.स.)। लोकसभा में बुधवार को *विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026* को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। संयुक्त समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। इन्हें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति नामित करेंगे। समिति को विधेयक की जांच और शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने आज विधेयक को संयुक्त समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा। विपक्षी दलों ने विधेयक को वापस लिए जाने की मांग की। सत्ता पक्ष ने कहा कि विधेयक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। इसके बाद -शेष पृष्ठ दो पर

फैंसी बाजार में नहीं सजेंगी फुटपाथियां दुकानें, विरान हो जाएंगी एसएस रोड, एमएस रोड, एचबी रोड

ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए कौशिक राय की अध्यक्षता में हुई बैठक

गुवाहाटी। आज जनता भवन के ब्लॉक बी स्थित ऑफिस कांफ्रेंस हॉल में, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौशिक राय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में फैंसी बाजार, खासकर एसएस रोड, एमएस रोड और एचबी रोड पर लगातार होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि एसएस रोड, एमएस रोड और एचबी रोड को *नो वेंडिंग जोन* घोषित किया जाएगा। साथ ही, ट्रैफिक की

आवाजाही को आसान बनाने और पैदल चलने वालों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन सड़कों पर गाड़ियों की पार्किंग पर रोक लगाई जाएगी। मंत्री ने जोर दिया कि इन उपायों को लागू करने से पहले व्यापारियों, वेंडरों, यात्रियों और आम जनता के बीच काफी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। इन उपायों को लागू करने से पहले एक औपचारिक नोटिस भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा, यह भी तय किया गया कि जल्द ही गुवाहाटी सेंट्रल के विधायक, -शेष पृष्ठ दो पर

doorgraph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है।
- आचार्य चाणक्य

असम बाढ़ : सीएम शर्मा ने किया हजार करोड़ के महापैकेज का एलान

गुवाहाटी। असम सरकार ने 19 जुलाई से ऊपरी असम के शिवसागर, चराईदेउ और जोरहाट जिलों में आई असामान्य बाढ़ के बाद राहत, सहायता और पुनर्वास कार्यों के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा की कि एक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। अब तक, 960 सर्वेक्षकों ने 8,325 परिवारों का सर्वे पूरा कर लिया है और दूसरा चरण चल रहा है। उम्मीद है कि सर्वे की प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सर्वे पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा और बाढ़ से प्रभावित लोग लाभार्थियों की विस्तृत सूची देख सकेंगे। जिन लोगों का नाम शुरू में छूट जाएगा, उन्हें सर्वे पूरा होने के बाद भी सूची में शामिल होने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने उन इलाकों में *मुख्यमंत्री राहत कोष* का इस्तेमाल करके हाउसिंग कॉलोनी बनाने की योजना का भी संकेत दिया, जहां बाढ़ से घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए इंश्योरेंस से मुआवजा पाने के हकदार लोगों से अपने क्लेम फाइल करने को कहा और बैंक लोन चुकाने में छह महीने की मोहलत या समय बढ़ाने के लिए 30 अगस्त तक आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूलों को फिर से चालू करने की कोशिशें चल रही हैं और सरकार का लक्ष्य 15 अगस्त तक पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियां शुरू करना है। इस काम में मदद के लिए 793 स्कूलों में से हर एक को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। असम की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार पवित्र *भादो* महीने के दौरान *नाम प्रसंग* में मदद के लिए हर *नामघर* को 1.50 लाख रुपए देने की योजना बना रही है। सरकार बाढ़ की स्थिति का फायदा उठाकर पैसे कमाने या ऐतिहासिक रूप से एकजुट रहे असमिया समाज में फूट डालने वाली किसी भी नकारात्मक गतिविधि या टिप्पणी पर कड़ी नजर रखेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि 72 यूट्यूबर ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए फंड इकट्ठा किया है।

सुवेंदु ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 10 करोड़ का बड़ा फंड

कोलकाता। असम में बाढ़ की स्थिति को *डरावना* बताते हुए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को पड़ोसी राज्य की इस संकट से निपटने में मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। अधिकारी ने कहा कि असम में बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और पश्चिम बंगाल का असम के साथ *खास आध्यात्मिक संबंध* है। अधिकारी ने -शेष पृष्ठ दो पर

मुख्यमंत्री ने असम बाढ़ रणनीति में बदलाव के संकेत दिए

गुवाहाटी। असम के ऊपरी हिस्से में अभूतपूर्व बाढ़ से नई कमजोरियां उजागर होने के बाद, असम सरकार ने बुधवार को कहा कि वह अपनी बाढ़ प्रबंधन रणनीति को फिर से तैयार करेगी और प्रभावित जिलों में हस्तक्षेप बढ़ाएगी। अब से इन दोनों जिलों में हस्तक्षेप किया जाएगा और हम इस साल की तुलना में कहीं अधिक तैयार रहेंगे। एक बार जब हम ऊपरी असम के जिलों में काम शुरू कर देंगे, तो हमें विश्वास है कि हम नुकसान को कम से कम करने में सक्षम होंगे, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को लोक सेवा भवन में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा। शर्मा ने यह भी सुझाव दिया कि आने वाले वर्षों में असम के बाढ़ के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है, जिससे खतरा -शेष पृष्ठ दो पर

अरुणाचल मामले पर चीन का पहला रिएक्शन

बॉर्डर पर हालात ठीक हैं

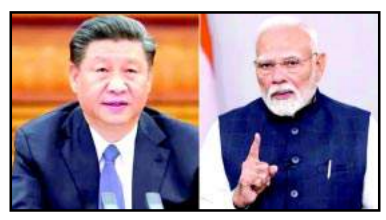

बीजिंग। चीन ने बुधवार को कहा कि चीन-भारत सीमा पर हालात फिलहाल आम तौर पर स्थिर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ने की खबरों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनसे पूछा गया था कि क्या हाल ही में भारत के साथ कोई सैन्य घटना हुई है और क्या चीन ने उस राज्य के पास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। गुओ ने कहा कि चीन-भारत सीमा पर हालात फिलहाल आम तौर पर स्थिर हैं। उन्होंने बताया कि चीन और भारत ने पिछले हफ्ते चीन-भारत सीमा मामलों पर बातचीत और समन्वय के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की 36वीं बैठक की -शेष पृष्ठ दो पर

रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा नया बिल लाने पर अमेरिका को चीन की चेतावनी

वॉशिंगटन (हि.स./रिया नोवोस्ती)। अमेरिका की तरफ से रूस पर प्रतिबंध लगाने के नए विधेयक को आगे बढ़ाने पर चीन ने चेतावनी दी है कि बीजिंग अपने वैध हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। अमेरिका में स्थित चीनी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि चीन ऐसे प्रतिबंधों का विरोध करता है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू चांग ने मंगलवार को रिया नोवोस्ती को बताया कि अगर अमेरिका मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़ा नया बिल लाता है- जिसके तहत रूस से ऊर्जा संसाधन खरीदने पर ड्यूटी (टैक्स) लगाई जाएगी तो चीन अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि चीन ऐसे एकतरफा प्रतिबंधों का कड़ा विरोध करता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है या जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी नहीं मिली है। अपने व्यवसाय और नागरिकों के वैध अधिकारों और हितों की मजबूती से रक्षा करने के लिए चीन जरूरी कदम उठाएगा। पिछले हफ्ते, सीनेट ने दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम (जिन्हें रूस में आतंकवादी और चरमपंथी माना जाता है) द्वारा पेश किए गए बिल को 86-11 वोटों से मंजूरी दी।

घाटकोपर में पहाड़ी धसकी मलबा घरों पर गिरा, छह की मौत

मुंबई (हि.स.)। मुंबई के उपनगर घाटकोपर के अशोक नगर में बुधवार को तड़के पहाड़ी का हिस्सा धसककर गौसिया चॉल के छह घरों पर गिर जाने से 6 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और पुलिस जवान राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त ने बताया कि यह हादसा तड़के करीब सवा तीन बजे का है। भूस्खलन के मलबे से अब तक 6 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी करीब छह लोगों के दबे होने की आशंका है। मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने बताया कि मलबे की चपेट में कई घर आए हैं। इलाके के कुछ घरों को नोटिस जारी -शेष पृष्ठ दो पर

अरुणाचल सीमा विवाद में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग, सीएम ने जल्द समाधान का दिया भरोसा

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से हालिया सीमा घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा से सटे पांच क्षेत्रों के 52 गांवों के लोगों की समस्याओं का अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि असम-अरुणाचल सीमा से जुड़े सभी मुद्दों का जल्द ही पूरी तरह समाधान कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नामघरों को 20 अगस्त से पहले डेढ़-डेढ़ लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में बाढ़ से घर पूरी तरह नष्ट हुए हैं, वहां मॉडल आवासीय परियोजनाएं शुरू की -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर में नगा गांव पर हमला, नौ घर जलाए गए, चर्च में भी लगाई आग

इंफाल। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में एक नगा गांव पर हुए हमले में कम से कम नौ घर जलाए गए। नगा संगठनों का दावा है कि इस आगजनी में एक चर्च को भी आग के हवाले किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह घटना मंगलवार रात लगभग 9:30 बजे टोकपा लियांगमाई नगा गांव में हुई। वर्दीधारी सशस्त्र लोगों ने स्वचालित बंदूकों से पहले अंधाधुंध गोलीबारी की और फिर उसके बाद गांव के ज्यादातर कच्चे ढांचों वाले नौ घरों को आग लगाकर राख कर दिया। बताया जाता है कि टोकपा लियांगमाई नगा गांव में कई घर धू-धूकर जलने पर वहां एक नजदीकी गांवों के निवासियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मदद की। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को -शेष पृष्ठ दो पर

पाकिस्तानी सेना ने सो रहे लोगों पर बरसाए बम, नौ बच्चों सहित 28 लोगों की मौत

पेशावर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य एयरस्ट्राइक ने पूरे इलाके को दहला दिया है। सुराब जिले के गोअनधान गांव में रात करीब 2 बजे हुए हमले में 28 नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। मृतकों में 9 बच्चे और 7 महिलाएं शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। सामने आई तस्वीरों और रिपोर्टों में मकानों के मलबे के बीच शवों और घायलों का जिक्र है। पाकिस्तानी सेना की ओर से इस हमले पर अभी तक आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना बलूचिस्तान के सुराब जिले के गोअनधान गांव में हुई। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी हवाई हमला हुआ। हमले के बाद कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा और बड़ी संख्या में -शेष पृष्ठ दो पर

सरकार संसद में नीट परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन पर चर्चा को तैयार : अमित शाह

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि सरकार संसद में नीट परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से चर्चा कर इस विषय पर पर्याप्त समय आवंटित करने का अनुरोध किया है। अमित शाह ने पत्र में कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आग्रह पर पहले ही संसद के मौजूदा सत्र में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन -शेष पृष्ठ दो पर

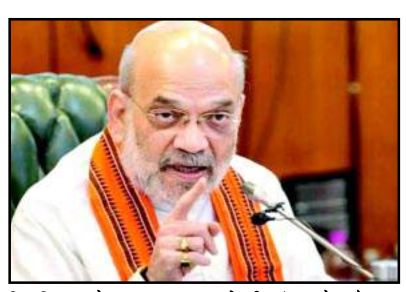

भाषण नहीं, छात्रों पर कार्रवाई का जवाब चाहिए : राहुल गांधी

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संसद में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए सरकार के तैयार होने और विपक्ष को 24 घंटे का समय देने के बयान पर -शेष पृष्ठ दो पर

सड़क हादसे के बाद 10 मिनट में पहुंचेगी एंबुलेंस, देरी हुई तो लगेगा दस हजार का जुर्माना

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना होने पर घायलों को तुरंत एंबुलेंस की सुविधा मिल सके, इसके लिए वैसे तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम-कंप्यूटर एडेड डिस्पैच (ईआरएस-सीएडी) पहले ही शुरू कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्राधिकरण के सामने जब लापरवाही की शिकायतें आईं तो अब सुधार के लिए और सख्त कदम उठाए गए हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) में दंड प्रविधान कड़े किए गए हैं। हर गलती पर सजा का प्रविधान है। अब यदि एंबुलेंस हादसे की सूचना -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
94350-14771

सीएम डॉ. शर्मा ने गुवाहाटी बाढ़ के पीछे कई विफलताओं का जिक्र किया

गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को गुवाहाटी में बार-बार आने वाली बाढ़ को लेकर मेघालय की अपनी पिछली आलोचना को नरम करते हुए कहा कि केवल पड़ोसी राज्य को दोष देने से शहर की जलभराव की समस्या का समाधान नहीं होगा। लोक सेवा भवन में प्रेस से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि दिसपुर और उसके आसपास के जिन इलाकों में बाढ़ का पानी जमा होता है, वे मेघालय से आने वाले जल प्रवाह से प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, हम सारा दोष मेघालय पर नहीं डाल सकते। यह समझाते हुए कि ध्यान दोषारोपण से समाधानों की ओर क्यों केंद्रित होना चाहिए, शर्मा ने जोरबाट बाढ़ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सशक्त समिति की एक रिपोर्ट की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि समिति ने पाया है कि जोरबाट में आरक्षित वन के नष्ट होने से असम-मेघालय सीमा पर बाढ़ की स्थिति और खराब हो रही है। जोराबत से बहकर आने वाले पानी को नियंत्रित करने का कोई उपाय किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए, हमें मेघालय में ही इसका समाधान ढूंढना होगा। हमें उस जंगल को पुन: प्राप्त करना होगा। हम सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए याचिका भी दायर करेंगे, उन्होंने कहा। राज्य के अन्य हिस्सों में हाल ही में आई बाढ़ से तुलना करते हुए, शर्मा ने कहा कि कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि गुवाहाटी के आसपास की पहाड़ियों से कितना पानी बहता होगा जब नगालैंड से आने वाले पानी ने ऊपरी असम में इतनी तबाही मचाई थी। हालांकि, शर्मा ने राज्य सरकार के भीतर की खामियों को भी स्वीकार किया और कहा कि इंजीनियरों द्वारा खराब पर्यवेक्षण के कारण कई नालियां अप्रभावी रह गई हैं। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी की नालियों का उद्देश्य पानी को निर्धारित चैनलों तक पहुंचाना है, लेकिन इसके बजाय वे उल्टा असर डाल रही हैं। सरकार की ओर से चूक और गलतियां हुई हैं, क्योंकि इंजीनियर नाली निर्माण में लगे ठेकेदारों की ठीक से निगरानी करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण जल निकासी व्यवस्था अप्रभावी हो गई है। मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में बाढ़ के एक अन्य कारण के रूप में नागरिक व्यवहार, विशेष रूप से कचरा निपटान को भी रेखांकित किया, और इसके उदाहरण के रूप में मालिगांव क्षेत्र का जिक्र किया। मालिगांव में भीषण बाढ़ की सूचना मिलने पर हमने पाया है कि बाजारों से कचरा नालियों में बहाया जा रहा है। हमें यह भी पता लगाना होगा कि इन नालियों से बरामद कचरा कहां से आ रहा है। हमें स्थानीय समाधानों की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। गुवाहाटी में शहरी और कृत्रिम बाढ़ से निपटने के लिए एक *नागरिक आंदोलन* का आह्वान करते हुए, शर्मा ने कहा कि शहर को अपशिष्ट निपटान और वर्षा जल संचयन के लिए बेहतर योजना की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्षाजल संचयन और कचरे को नालियों में बहाने से रोकना आवश्यक है।

आईएसआई से संबंध के संदेह में हाबरा से पाकिस्तानी नागरिक सहित दो गिरफ्तार

कोलकाता (हि.स.)। स्वतंत्रता दिवस से पहले पश्चिम बंगाल में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक सहित दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर 24 परगना के हाबरा से राज्य पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पाकिस्तान के नागरिक वहाब आलम उर्फ राना रऊफ बताया गया है। उससे पूछताछ के बाद कोलकाता के तपसिया इलाके से मोहम्मद इजाज नामक एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि इजाज, राना के सहयोगी के रूप में काम करता था। प्राथमिक तौर पर इन दोनों के संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से होने का संदेह है। जांच से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि राना पाकिस्तानी सेना से जुड़ा हुआ है। वह आईएसआई के हैंडलर के रूप में काठमांडू के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। जांचकर्ताओं को पता चला है कि वह इससे पहले भी कई बार भारत आ चुका था। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार, वहाब आलम उर्फ राना तपसिया इलाके में रहता था और वहां छोटे-मोटे काम करता था। उसने *वहाब* नाम से आधार कार्ड समेत कई फर्जी पहचान पत्र बनवाए थे। इस काम में इजाज ने राना की मदद की थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के *हैंडलर* के रूप में राना मुख्य रूप से काठमांडू से अपनी गतिविधियां संचालित करता था। हालांकि काम के सिलसिले में वह अक्सर भारत आता था। हाल ही में वह काकरभिट्टा सीमा के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। आरोप है कि राना मुख्य रूप से भारतीय सेना और रेलवे के बुनियादी ढांचे पर नजर रखकर सूचनाएं एकत्र करता था। इन सूचनाओं को पाकिस्तान भेजा जाता था। इसके अलावा राना ने किसी तरह की आतंकी गतिविधि की साजिश रची थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इससे पहले 30 जुलाई को आतंकी संबंधों के आरोप में एसटीएफ ने बर्दवान से हामिम मंडल नामक एक युवक को गिरफ्तार किया था। हामिम के साथ उसकी कथित प्रेमिका अर्पिता सरकार और आदित्य सिंह उर्फ राज नामक एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उनके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गिरोह से नियमित संपर्क थे।

तामुलपुर में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के जिला मुख्यालय भवन का शिलान्यास

तामुलपुर(हिंस)। तामुलपुर दुर्गा मंदिर के समीप बुधवार को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के जिला मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। बोड़ोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की कार्यकारी सदस्य मुनमुन ब्रह्म ने बीटीसी के कार्यकारी सदस्य महेश्वर बसुमतारी और पूर्व विधायक इमैनुएल मुसाहारी की उपस्थिति में भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुनमुन ब्रह्म ने कहा कि तामुलपुर एक बेहद संभावनाशील जिला है और यहां विकास के लिए काफी कार्य किए जाने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से जिले के विकास के लिए बेहतर कार्य करने को लेकर वह आशावादी हैं। करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित दो मंजिला भवन के निर्माण के लिए प्रारंभिक चरण में 70 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। कार्यकारी सदस्य ने शिलान्यास स्थल के परिसर में स्थित हैंडलूम को-ऑपरेटिव सोसाइटी के प्रशिक्षण भवन में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की भी वकालत की।

स्वतंत्रता दिवस : फिक्की और मारवाड़ी मैटरनिटी अस्पताल ने आयोजित किया रक्तदान अभियान

गुवाहाटी (हिंस)। स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत फिक्की, नार्थ ईस्ट और मारवाड़ी मैटरनिटी अस्पताल के सहयोग से आज रक्तदान अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान सेवा भावना और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक पहल रहा। इस पहल के माध्यम से समुदाय की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उद्योग और नागरिक समाज के बीच सहयोग की भावना को भी बढ़ावा दिया गया। अभियान में फिक्की से जुड़े सदस्यों तथा मारवाड़ी मैटरनिटी अस्पताल की चिकित्सा टीम ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान का एक छोटा-सा प्रयास किसी जरूरतमंद की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

असम में अभी भी बाढ़ से 441 गांव घिरे, 112718 नागरिक प्रभावित

गुवाहाटी (हिंस)। असम में अभी भी बाढ़ से 441 गांव घिरे हैं और 112718 नागरिक प्रभावित हैं। नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रह है।इससे कई जिलों में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। मगर कई जिलों में बाढ़ का असर अब भी है। यहां के प्रभावित लोग राहत शिविरों के साथ ही तटबंधों पर प्लास्टिक के टेंट में आश्रय लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा प्रतिदिन समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को हर संभव कदम उठाने का निर्देश दे रहे हैं। वह मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। स्वयंसेवी संगठन एवं निजी स्तर पर भी लोग प्रभावितों की मदद में जुटे हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 11 अगस्त के आंकड़ों के अनुसार, धनसिरि नदी (नुमलीगढ़) तथा कुसियारा नदी (श्रीभूमि) इलाके में खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही है। अब तक बाढ़ से 102 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी गोलाघाट, शिवसागर, होजाई, जोरहाट, दरंग, लखीमपुर और नगांव जिला बाढ़ से घिरे हुए हैं। इन जिलों के 25 राजस्व मंडलों के कुल 441 गांव प्रभावित हैं। वर्तमान समय में राज्य के कुल 112718 नागरिक बाढ़ से प्रभावित हैं।

विदेशी फंडिंग पर नजर रखने के लिए एफसीआरए जरूरी : रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज बुधवार, 12 अगस्त को सदन में बोलेते हुए विदेशी फंडिंग रेगुलेटरी बिल (एफसीआरए) के खिलाफ विपक्ष के गुमराह करने वाले अभियान की कड़ी आलोचना की। किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है और विदेशी फंड खर्च करने के लिए नियम-कानून होने चाहिए। कुछ एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग के रेगुलेशन में कमियों को दूर करने और धर्म-परिवर्तन को रोकने के मकसद से लाए गए इस प्रस्तावित कानून की विपक्ष आलोचना कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह अल्पसंख्यक-विरोधी विधेयक है। विदेशी पूंजी के प्रवाह पर नजर रखने वाले इस एफसीआरए बिल को लोकसभा ने जेपीसी के पास भेज दिया।

पृष्ठ एक का शेष

जेपीसी को भेजा गया ...

विधेयक को ध्वनिमत से जेपीसी को भेजे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इससे अल्पसंख्यक संस्थानों की विदेशी फंडिंग रुक जाएगी। सपा नेता अखिलेश यादव ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए कहा कि पूरा विपक्ष इस विधेयक के विरोध में है। द्रमुक नेता टीआर बालू ने भी कहा कि विधेयक को वापस लिया जाए। दूसरी ओर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने ही विधेयक को जेपीसी में भेजे जाने की मांग रखी थी। उन्होंने कहा कि कोई विषय है तो उसे जेपीसी में रखा जा सकता है। विपक्ष इसका स्वागत करने की जगह विरोध कर रहा है। यह देश को सुरक्षित रखने की बात है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का सवाल ही नहीं है। नियम और संवैधानिक व्यवस्था के लिए कानून जरूरी है। सरकार के पत्र सूचना कार्यालय का कहना है कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) को लेकर कई धारणाएं अधूरी जानकारी पर आधारित हैं। एफसीआरए विदेशी चंदे पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता बल्कि पंजीकरण और पारदर्शिता की शर्तों के साथ इसकी अनुमति देता है। वर्ष 2024-25 में करीब 16,200 पंजीकृत संगठनों को लगभग 22,963 करोड़ रुपए का विदेशी अंशदान मिला। कानून केवल गैर सरकारी या धार्मिक संगठनों तक सीमित नहीं है और धर्म, समुदाय या विचारधारा के आधार पर भेद नहीं करता। पंजीकरण गतिविधियों पर पूर्व अनुमति की व्यवस्था नहीं बनाता। संपत्तियों से जुड़े प्रावधान केवल विदेशी अंशदान से बनी संपत्तियों पर लागू होते हैं। पंजीकरण रद्द होना हमेशा किसी गलती का प्रमाण नहीं होता क्योंकि प्रशासनिक कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं।

फैंसी बाजार में नहीं सजेंगी...

कामरूप मेट्रोपॉलिटन के जिला आयुक्त, जीएमसी के आयुक्त और कामरूप मेट्रोपॉलिटन के डीटीओ (एनफोर्समेंट) के साथ एक और बैठक की जाएगी। इस बैठक में उपायों को लागू करने की विस्तृत रणनीति और तौर-तरीकों पर चर्चा होगी। इस पहल का मकसद फैंसी बाजार को ज्यादा व्यवस्थित, सुरक्षित और जाम-मुक्त बनाना है। साथ ही, इसका उद्देश्य यात्रियों और पैदल चलने वालों के लिए बेहतर आवाजाही सुनिश्चित करना और गुवाहाटी के सबसे व्यस्त कमर्शियल इलाकों में से एक में व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना है। मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे प्रस्तावित उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपस में मिलकर काम करें और इस दौरान जनता, व्यापारियों और बिजनेस कम्युनिटी के हितों का भी ध्यान रखें। बैठक में गुवाहाटी सेंट्रल के विधायक विजय कुमार गुप्ता, गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (जीएमसी) के मेयर मृगेन सरनिया, जीएमसी के आयुक्त चिन्मय प्रकाश फूकन, असम पुलिस के एडीसीपी (ट्रैफिक-2) मृण्मय गोस्वामी, एसीपी ट्रैफिक-2 दीपज्योति दधारा (एपीएस), जीएमसी के डिप्टी मेयर और पार्षद, जीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी और फैंसी बाजार समिति के प्रतिनिधि शामिल हुए।

सुवेंदु ने मुख्यमंत्री ...

बुधवार को विधानसभा में कहा कि पड़ोसी राज्य असम में स्थिति डरावनी है। असम के साथ हमारा खास आध्यात्मिक संबंध है। मणिपुर और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने असम को मदद देने की घोषणा की है। हम भी मुख्यमंत्री राहत कोष से असम को 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। इससे पहले दिन में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि बाढ़ की हालिया लहर से बुरी तरह प्रभावित जिलों में संपत्तियों की मरम्मत और बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्वास प्रक्रिया में पूरी मदद का भरोसा दिया है। शर्मा ने कहा स्थायी राहत देने के लिए 9 अगस्त को तेजी से राहत का आकलन करने का अभियान शुरू किया गया था। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, 8,000 से ज्यादा परिवारों का आकलन किया गया है और 150 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। शर्मा ने कहा कि यह सर्वे 30 अगस्त तक जारी रहेगा और उम्मीद है कि इसमें ऊपरी जिलों के 50,000-60,000 परिवार शामिल होंगे, जो हालिया बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। शर्मा ने कहा मेरा मानना है कि नुकसान की मरम्मत और पुनर्वास में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। पीएम ने भरोसा दिलाया है कि प्रभावित परिवारों को भुगतान करने में कोई दिक्कत नहीं है और हमसे कहा है कि बिना किसी चूक के आकलन करें। प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अलग-अलग ग्रुप्स से मिले सहयोग को मानते हुए, उन्होंने कहा कि देश भर के 72 यू ट्यूबर्स ने इस काम के लिए फंड इकट्ठा किया है। उन्होंने कहा कि उनमें से कई पहले से ही जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। हम इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि क्या वे बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। शर्मा ने ऊपरी असम में बाढ़ से क्षतिग्रस्त 494 आंगनवाड़ी केंद्रों के पुनर्निर्माण के लिए 11.3 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये केंद्र जल्द से जल्द फिर से शुरू हों ताकि सभी सेवाएं दी जा सकें। इस अभियान में कुल 494 क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी केंद्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने असम ...

ब्रह्मपुत्र से हटकर उसकी सहायक नदियों की ओर स्थानांतरित हो सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ का सामना कर रहे जिलों में बाढ़ की स्थिति में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका मुख्य कारण तिब्बत में बड़े जलाशयों और अरुणाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं सहित कई विकास कार्य चल रहे हैं। इससे आने वाले कुछ वर्षों में ब्रह्मपुत्र में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में बाढ़ नियंत्रण उपायों को ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी, जो उनके अनुसार इस वर्ष ऊपरी असम में हुई तबाही के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थीं। हमने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और अधिकांश बाढ़ उन क्षेत्रों में आ रही हैं जहां दिखो और डोरिका जैसी सहायक नदियों का प्रभुत्व है, शर्मा ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि शिवसागर में आई बाढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के कारण नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियों के कारण थी। जल संसाधन विभाग को इन सहायक नदियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि बाढ़ से बचाव के उपायों से कई ऐसे जिलों में सकारात्मक परिणाम मिले हैं जो पारंपरिक रूप से बाढ़ के प्रति संवेदनशील रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण, इस बार उन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आई है जहां आमतौर पर बाढ़ आती है। नलबाड़ी, बाक्सा, बोजाली, विश्वनाथ और बिहपुरिया में बाढ़ नहीं है, जबकि धेमाजी और लखीमपुर में नुकसान सीमित रहा है। हालांकि, हालिया बाढ़ ने ऊपरी असम के उन हिस्सों में नई कमजोरियों को उजागर किया है जहां ऐतिहासिक रूप से बड़ी बाढ़ की घटनाएं कम ही होती थीं। उन्होंने शिवसागर और चराईदेउ का जिक्र करते हुए कहा कि असम के अधिकांश हिस्सों में सफलता मिली है, लेकिन चूंकि दो जिलों में पहले बाढ़ की समस्या नहीं थी, इसलिए हमने वहां हस्तक्षेप नहीं किया। सरकार ने उन क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाले जल निकासी पंप भी तैनात किए हैं जहां अभी भी बाढ़ का पानी जमा है। उन्होंने बताया कि शिवसागर जिले में ये पंप प्रति घंटे लगभग 1.35 लाख लीटर पानी निकाल रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वीटी चांगसन के अनुसार, 49 तटबंध टूट गए थे, 104 प्रभावित हुए थे, 36 पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे और 1,187 सड़कें प्रभावित हुई थीं। मुख्यमंत्री की प्रेस कांफ्रेंस से पहले मीडिया को जानकारी देते हुए चांगसान ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, हालांकि हजारों लोग अभी भी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में सात जिले और 25 राजस्व सर्कल प्रभावित रहे, जबकि 1.12 लाख से अधिक लोग अभी भी इससे प्रभावित हैं। कुल 47 राहत शिविर कार्यरत हैं और उनमें 7,982 लोग शरण लिए हुए हैं। चांगसन ने कहा कि शिवसागर में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं, जहां जिले में 50 लोगों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), भारतीय सेना, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और अन्य एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से 21,726 लोगों को बचाया गया है। एएसडीएमए के अनुसार, चराईदेउ दूसरा सबसे अधिक प्रभावित जिला था, जहां 22 लोगों की मौत हुई। वहां के सभी विस्थापित निवासी अपने-अपने घर लौट चुके हैं और अब कोई भी राहत शिविर कार्यरत नहीं है। चांगसान ने बताया कि जोरहाट में नौ मौतें दर्ज की गईं, जिनमें से दो शहरी बाढ़ से संबंधित थीं, जबकि गोलाघाट में आठ मौतें हुईं। मौजूदा हालात में सुधार होने के साथ ही, सरकार का ध्यान अब उन क्षेत्रों में बाढ़ से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने की ओर केंद्रित हो रहा है जो इस वर्ष की बाढ़ के दौरान नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरे थे।

बॉर्डर पर हालात ठीक...

थी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत जारी रखने और सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। भारत ने मंगलवार को कहा कि वह चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों से जुड़े मामलों को बेहद गंभीर मानता है और इस बात पर जोर दिया कि लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि सीमा की स्थिति ही दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगी। यह बयान अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी इलाके में चीनी सैनिकों के आक्रामक रवैये की खबरों के बीच आया है। नई दिल्ली ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं की आधिकारिक तौर पर उनके मानक नामों से पहचान करने के अपने फैसले पर बीजिंग की आलोचना को भी खारिज कर दिया। भारत ने जोर देकर कहा कि यह राज्य भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है और कोई भी चीज इस अविवादित सच्चाई को बदल नहीं सकती।

अरुणाचल सीमा विवाद...

जाएंगी। जिन क्षेत्रों में मवेशियों का नुकसान हुआ है, वहां पशुधन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इन क्षेत्रों को दुग्ध उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 72 यूट्यूबरों ने बाढ़ के नाम पर धन संग्रह किया था। सरकार इस बात पर नजर रख रही है कि संग्रहित धन वास्तव में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा है या नहीं। उन्होंने समय गोगोई जैसे यूट्यूबरों द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करना सरकार का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने शिवसागर और चराईदेव जिलों के लोगों से अस्थायी ईएमआई राहत के लिए 30 अगस्त तक बैंकों में आवेदन करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित चार जिलों के लोगों से जल्द से जल्द बीमा दावे दाखिल करने की अपील की। उधर धेमाजी जिलांतर्गत गोहपुर (असम-अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती) के राजगढ़ में बुधवार को भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने अरुणाचल प्रदेश के सड़क मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। यह प्रदर्शन धेमाजी जिले के गोगमुख में मिंगमांग बदाती इलाके में अरुणाचल प्रदेश के लोगों द्वारा कथित तौर पर अंधाधुंध गोलीबारी किए जाने के विरोध में किया गया। यह विरोध प्रदर्शन ट्राइबल माइग्रेंट्स प्रोटेक्शन कमिटी (टीएमपीके) और कई स्थानीय संगठनों ने मिलकर आयोजित किया था। उन्होंने दो दिन पूर्व हुई गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने घटना की निंदा करते हुए नारे लगाए और प्लेकार्ड दिखाए। साथ ही, उन्होंने आरोपितों की तुरंत गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की। इस घटना के बाद धेमाजी में जिला-व्यापी बंद की मांग भी उठी है, क्योंकि संगठनों और स्थानीय निवासियों ने गोलीबारी का विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों ने असम-अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती इलाके में ऐसी घटनाओं के बार-बार होने पर चिंता जताई और प्रशासन से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अंतर-राज्यीय सीमा पर सुरक्षा के और मजबूत इंतजाम करने की भी मांग की। ज्ञात हो कि बीते दिनों इलाके में हुई गोलीबारी में असम के लगभग 11 व्यक्तियों के घायल होने का दावा किया गया था। जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच दोनों राज्यों की सरकारें इस घटना को लेकर एक-दूसरे के संपर्क में हैं, साथ ही घटना की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं।

मणिपुर में नगा गांव ...

तैनात किया गया है। मणिपुर में लियांगमाई नगा काउंसिल ने इस घटना की निंदा की और आरोप लगाया कि हमले के पीछे एक अन्य समुदाय के सशस्त्र लोग थे। काउंसिल ने दावा किया कि हमले में 10 घर और एक चर्च जलाए गए हैं। इसने एक बयान में कहा कि निर्दोष नागरिकों, आवासीय संपत्तियों और प्रार्थनास्थल को जानबूझकर निशाना बनाना एक गंभीर और निंदनीय हिंसा का कार्य है। नगा संगठन ने आगजनी के लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी और अभियोजन की मांग की। इसने क्षेत्र में सुरक्षा को तुरंत मजबूत करने की भी मांग की। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही ठीक इसी तरह कुकी समुदाय के एक गांव में घर जलाए गए थे। मणिपुर के उखरुल जिले में कुकी संगठनों के एक समूह ने राज्य के गृह मंत्री गोविंदास कोन्थौजम से बातचीत के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-202 पर दो सप्ताह से अधिक समय से चल रहे अवरोध को हटा लिया है। कुकी सीएसओ वर्किंग कमेटी उखरुल (केसीडब्ल्यूसी) ने 27 जुलाई को कुछ समुदायों द्वारा जिले के कुकी क्षेत्रों में *चयनात्मक आर्थिक अवरोध* के विरोध में *काउंटर अवरोध* लगाया था। गृह मंत्री कोन्थौजम ने कहा कि अब मालवाहक वाहन एनएच-202 से उखरुल की ओर अपनी यात्रा फिर शुरू कर चुके हैं।

घाटकोपर में पहाड़ी...

किए गए थे। अब पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी। उपनगर जिलाधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी के अनुसार, प्रशासन की पहली प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और आसपास के जोखिम वाले घरों को सुरक्षित करना है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

पाकिस्तानी सेना ने सो ...

लोग मलबे में दब गए। स्थानीय स्तर से सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस हमले में 28 नागरिकों की मौत हुई है। इनमें 9 बच्चे, 7 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 17 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों और वीडियो को लेकर रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कई शव मलबे के नीचे दबे मिले। कुछ पीड़ितों की उम्र बेहद कम बताई जा रही है। इससे इस कार्रवाई में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घायलों को स्थानीय स्तर पर इलाज के लिए ले जाया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। इस घटना को बलूचिस्तान में पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों और आजादी की मांग के बीच देखा जा रहा है। बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन लंबे समय से सक्रिय है और पाकिस्तान सरकार तथा सेना पर बलूच नागरिकों के खिलाफ दमन करने के आरोप लगते रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना तथा दूसरे खनिज संसाधनों से बेहद समृद्ध माना जाता है। इसके बावजूद वहां लंबे समय से गरीबी, बेरोजगारी और विकास की कमी को लेकर शिकायतें रही हैं। बलूच संगठनों का आरोप है कि प्रांत के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को पर्याप्त रूप से नहीं मिलता। इसके अलावा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी भी लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहा है। बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का कहना है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में स्थानीय आबादी के हितों और अधिकारों की अनदेखी की गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर जबरन गुमशुदगी, हिरासत में यातना और कथित फर्जी मुठभेड़ों जैसे गंभीर आरोप लंबे समय से लगाए जाते रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और सेना बलूचिस्तान में चलाए जा रहे सैन्य अभियानों को आतंकवाद और सशस्त्र विद्रोह से निपटने की कार्रवाई बताती रही है। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और स्थानीय आबादी के बीच अविश्वास लगातार गहरा रहा है। सुराब की घटना को लेकर सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया पर है। रिपोर्ट के अनुसार, घटना के बाद इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी आईएसपीआर की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया।

सरकार संसद में नीट...

विधेयक, 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए फिर तैयार है। गृहमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि विपक्ष से चर्चा कर आपसी सहमति से आज से जितना समय और जितने घंटे उचित समझें, उतना समय इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के दौरान वह सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। शाह ने कहा कि लोकतंत्र में चर्चा और संवाद से ही समाधान निकलता है। उन्होंने कहा कि उन्हें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अटूट विश्वास है और उनका मानना है कि सदन चर्चा और संवाद के लिए ही है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से विपक्ष के नेताओं से चर्चा कर इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में अच्छा वातावरण बनाने का आग्रह किया ताकि पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य इस मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकें।

भाषण नहीं, छात्रों पर...

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष गृहमंत्री का भाषण सुनने में रुचि नहीं रखता। उनकी मांग केवल यह जानने की है कि दिल्ली में छात्रों पर गोली चलाने और उनके खिलाफ बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। राहुल गांधी ने बुधवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विपक्ष यह जानना चाहता है कि छात्रों पर गोली किसने चलाई, गोली चलाने का आदेश किसने दिया, एक छात्र की आंखों की रोशनी किस तरह गई और एक छात्र के कान में गोली किसने मारी। छात्रों पर लाठी चलाने और कथित तौर पर कीलों वाले डंडों के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया, इसका जवाब गृहमंत्री को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और आरएसी गृह मंत्रालय के अधीन हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने छात्रों पर कार्रवाई का आदेश दिया था या नहीं, उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए। अगर शाह ने आदेश दिया था तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी को लेकर इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि अमित शाह संसद में आकर क्या भाषण देंगे। विपक्ष छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर स्पष्ट जवाब चाहता है। पिछले 20 दिनों से गृहमंत्री संसद में इस मुद्दे पर सामने नहीं आए और अब सत्र के अंतिम दौर में चर्चा की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि गृहमंत्री सभी सवालों का जवाब देंगे लेकिन विपक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह किस सवाल का जवाब चाहता है। वह छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं और इस मुद्दे पर खुले तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े हर पहलू पर चर्चा के लिए तैयार है। शाह ने कहा कि विपक्ष बुधवार दोपहर तीन बजे तक लोकसभा अध्यक्ष को चर्चा के लिए पत्र दे तो सरकार तीन बजे से अगले दिन तीन बजे तक चर्चा कराने के लिए तैयार है और वह खुद पूरी चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहकर सभी सवालों का जवाब देंगे। मानसून सत्र शुरू होने के बाद से वह नियमित रूप से संसद आ रहे हैं और अपने कक्ष में मौजूद रहते हैं, लेकिन विपक्ष दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।

सड़क हादसे के बाद...

मिलने के बाद देरी से पहुंची तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, सूचना मिलते ही दो मिनट में न चली एंबुलेंस तो प्रति मिनट देरी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। एनएचएआई केयर सिस्टम के नियमों के तहत एंबुलेंस को सूचना की स्वीकृति के बाद 10 किलोमीटर के भीतर किसी भी हादसा स्थल पर पहुंचने में 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। नेशनल हाईवे पर तैनात एंबुलेंस, क्रेन और गश्ती वाहन के बेहतर प्रबंधन के लिए ही एनएचएआई ने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम शुरू किया था। इसके साथ ही इन सभी संबंधित वाहनों में एआईएस-140 जीपीएस उपकरण लगाए गए। प्रत्येक आन-रोड वाहन को आईओटी सिम लगा एंड्रायड मोबाइल दिया गया है। यह एनएचएआई केयर मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ा है जो कि दुर्घटनास्थल से संबंधित जानकारी सड़क पर तैनात वाहन तक पहुंचाता है और आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही सहित डाटा को एकत्र करता है। इसके अलावा प्रत्येक घटना प्रबंधक यानी इंसिडेंट मैनेजर को आईओटी सिम युक्त एंड्रायड टैबलेट दिया गया है। यह भी एनएचएआई केयर डैशबोर्ड एप्लिकेशन से जुड़ा है, जो कि आईएम को वाहनों को ट्रैक करने और दुर्घटना के प्रबंधन की रीयल टाइम मानीटरिंग में सहायता करता है। एक केंद्रीय काल सेंटर है जो 24 घंटे काम करता है।

नौकरी का झांसा देकर बंधक बनाई गई महिला 11 दिन बाद बरामद; एक गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। नौकरी दिलाने का झांसा देकर जागीरोड की एक महिला को गुवाहाटी के बरबाड़ी इलाके में कथित रूप से 11 दिनों तक बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। दिसपुर पुलिस ने महिला को एक मकान से सुरक्षित बरामद कर लिया। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी है। बुधवार को पुलिस ने बताया कि महिला को रोजगार दिलाने के बहाने गुवाहाटी लाया गया था। इसके बाद उसे कथित रूप से एक कमरे में बंद कर दिया गया। महिला ने किसी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई। महिला ने मंगलवार शाम करीब पांच बजे एक परिचित को व्हाट्सऐप संदेश भेजकर कथित तौर पर बताया कि उसे कमरे में बंद कर रखा गया है और रस्सी से बांधा गया है। उसने पुलिस को सूचना देकर उसे बचाने की अपील की।

यूपीपीएल प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से बीटीआर समझौता क्रियान्वयन की उठाई मांग

कोकराझाड़ (हिंस)। यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोड़ोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) शांति समझौता-2020 के सभी प्रावधानों को शीघ्र लागू करने तथा छठी अनुसूची के तहत आने वाली परिषदों को अधिक अधिकार देने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। यूपीपीएल सूत्रों ने आज यहां बताया कि यूपीपीएल के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद बोडो के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को संसद में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद रोंगवरा नार्जारी, लोकसभा सांसद जयंत बसुमतारी तथा यूपीपीएल के उपाध्यक्ष दीपेन बोडो शामिल थे। बैठक के दौरान

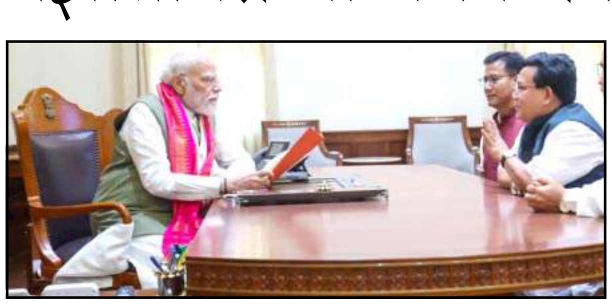

बीटीआर के विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से बीटीआर शांति समझौता-2020 के सभी प्रावधानों के शीघ्र क्रियान्वयन के साथ-साथ 125वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। यूपीपीएल नेताओं ने संविधान के अनुच्छेद 280 को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि बोड़ोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) सहित देश की सभी छठी अनुसूची परिषदों को वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से अधिक सशक्त बनाया जा सके। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को बीटीआर में लगातार उत्पन्न हो रही बाढ़ और कटाव की गंभीर समस्या से भी अवगत कराया। विशेष रूप से भूटान से आने वाली धाराओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए विशेष हस्तक्षेप की मांग की गई। बैठक के बाद यूपीपीएल अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को धैर्यपूर्वक सुना और बैठक बेहद सार्थक रही। उन्होंने कहा कि बीटीआर के विकास, समझौते के प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा क्षेत्र की बाढ़ एवं कटाव की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर आवश्यक सहयोग की उम्मीद है। प्रमोद बोडो ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हुए बीटीआर शांति समझौते ने क्षेत्र में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। अब समझौते के सभी प्रावधानों को निर्धारित रूप से लागू करना क्षेत्र के लोगों के हित में महत्वपूर्ण कदम होगा।

एलजीबीआई एयरपोर्ट ने इंटीग्रेटेड रेनवाटर हार्वेस्टिंग और इस्तेमाल की पहल के जरिए पानी की सस्टेनेबिलिटी को दिया बढ़ावा

गुवाहाटी (हिंस)। अपने सस्टेनेबिलिटी एजेंडा और *वॉटर पॉजिटिव* लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता के तहत, गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एलजीबीआई) ने पूरे एयरपोर्ट इकोसिस्टम में इंटीग्रेटेड वॉटर मैनेजमेंट अप्रोच के जरिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग और उसके इस्तेमाल पर अपना ध्यान और मजबूत किया है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) प्रबंधन ने आज बताया है कि गुवाहाटी में हर साल लगभग 1, 800-2, 200 एमएम बारिश होती है, जिससे बारिश का पानी एयरपोर्ट के सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों में से एक बन जाता है। बीते 9 अगस्त तक एयरपोर्ट पर लगभग 1, 320 एमएम बारिश हो चुकी है, जो बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने वाली समस्या से बदलकर पानी के एक टिकाऊ स्रोत में बदलने का एक बड़ा मौका देती है। इस पहल के तहत, एलजीबीआई एयरपोर्ट पर बारिश का पानी जमा करने के लिए दो बड़े टैंक हैं, जिनकी कुल क्षमता 1, 000 केएल है। जमा किए गए बारिश के पानी को एयरपोर्ट के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) में ट्रीट किया जाता है और फिर इसका इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जाता है, जैसे पीने के पानी के फाउंटेन, इक्विपमेंट की सफाई और कूलिंग टावर में पानी की जरूरत पूरी करना। पीने लायक बनाने के लिए, ट्रीट किए गए पानी को एडवांस्ड मल्टी-स्टेज ट्रीटमेंट और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि पानी पीने के लिए तय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे। अकेले जुलाई 2026 में, नए बने अत्याधुनिक टर्मिनल 2 में इस्तेमाल होने वाले कुल पानी का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा बारिश के जमा किए गए पानी से पूरा किया गया। यह इस पहल की बड़ी क्षमता को दिखाता है कि कैसे बाहरी पानी के स्रोतों पर निर्भरता कम करते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिले-जुले नजरिए में इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस (ईएंडएम), ईएसजी, ऑपरेशन्स और प्रोजेक्ट्स टीमों के बीच करीबी तालमेल शामिल है, जिससे बारिश के पानी को इकट्ठा करके, उसे ट्रीट करके एयरपोर्ट के कई कामों में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और मौजूदा व भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए, उम्मीद है कि यह पहल एयरपोर्ट की बढ़ती पानी की जरूरतों को टिकाऊ तरीके से पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। एलजीबीआई एयरपोर्ट पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने और उसके इस्तेमाल की पहल, एएएचएल नेटवर्क में अपनी तरह का पहला इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। इससे गुवाहाटी एयरपोर्ट टिकाऊ जल प्रबंधन के मामले में एक मिसाल बन गया है। इस पहल में एएएचएल नेटवर्क के दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी इसे लागू करने के लिए एक बेंचमार्क बनने की क्षमता है।

एसएसबी प्रथम वाहिनी का स्वतंत्रता दिवस पर भव्य पब्लिक बैंड डिस्प्ले 15 एवं 16 अगस्त को

गुवाहाटी (हिंस)। देशभर में मनाए जा रहे 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं *आजादी का अमृत महोत्सव* तथा *हर घर तिरंगा* अभियान के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), सीमांत मुख्यालय गुवाहाटी एवं सोनापुर स्थित प्रथम वाहिनी द्वारा आम नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र गौरव की भावना को और अधिक प्रबल करने के उद्देश्य से पब्लिक बैंड डिस्प्ले कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एसएसबी के ब्रास बैंड, जैज बैंड एवं पाइप बैंड द्वारा देशभक्ति एवं राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, युवाओं, विद्यार्थियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता रहेगी। एसएसबी प्रथम वाहिनी के द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार 15 अगस्त को गुवाहाटी के क्रिश्चियन बस्ती स्थित सिटी सेंटर मॉल में 1800 बजे से 2000 बजे तक पब्लिक बैंड डिस्प्ले किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आम नागरिकों के लिए नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। वहीं, 16 अगस्त को गुवाहाटी के उजान बाजार स्थित सती राधिका शांति उद्यान (ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट) में पब्लिक बैंड डिस्प्ले कार्यक्रम 1800 बजे से 2000 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आम नागरिकों के लिए गेट नंबर-06 एवं गेट नंबर-07 से नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। यह कार्यक्रम एसएसबी सीमांत मुख्यालय गुवाहाटी के महानिरीक्षक सुधीर वर्मा के मार्गदर्शन में तथा प्रथम वाहिनी के कमांडेंड सुनील कौशिक की निगरानी में आयोजित किया जा रहा है। एसएसबी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने तथा स्वतंत्रता दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एसएसबी सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वे इस भव्य पब्लिक बैंड डिस्प्ले कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर *हर घर तिरंगा* अभियान को सफल बनाने में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।

काजीरंगा के आसपास 10 किमी ईएसजेड से कलियाबर जखलाबंधा और बोकाखात प्रभावित होंगे : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) को लेकर राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी किए जाने तक मौजूदा 10 किलोमीटर का प्रावधान लागू रहेगा। मुख्यमंत्री ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के एक किलोमीटर के ईएसजेड संबंधी निर्देश का अर्थ यह नहीं है कि मौजूदा 10 किलोमीटर का प्रावधान तत्काल समाप्त या कम हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ईएसजेड की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद उसमें निर्धारित दूरी प्रभावी होगी। डॉ. शर्मा ने कहा कि काजीरंगा के आसपास 10 किलोमीटर का ईएसजेड बनाए रखने से कालियाबर, डबका, जखलाबंधा और बोकाखात जैसे आबादी वाले क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने लोगों से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पूरी तरह पढ़कर समझने की अपील करते हुए कहा कि अधूरी जानकारी के आधार पर इस मुद्दे पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। ईएसजेड की अधिसूचना की प्रक्रिया समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसे राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी। इसके बाद केंद्र सरकार प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पास भेजेगी। डॉ. शर्मा ने कहा कि सामान्य तौर पर ईएसजेड को एक किलोमीटर के दायरे में रखने का प्रावधान है, हालांकि परिस्थितियों के अनुसार इसे तीन किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने हाल में दिपर बील के आसपास अधिसूचित ईएसजेड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र की सीमा एक किलोमीटर निर्धारित की गई है। इसलिए हर जगह 10 किलोमीटर का ईएसजेड होना अनिवार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि काजीरंगा के आसपास 10 किलोमीटर का मौजूदा प्रावधान तब तक लागू रहेगा, जब तक राज्य सरकार ईएसजेड की औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं करती। अधिसूचना जारी होने के बाद उसमें निर्धारित दूरी ही प्रभावी होगी।

बाढ़ प्रभावित नाजिरा और डिमौ की 20 स्कूलों को रिनिकी भुइयां ने दी एक करोड़ की सहायता

गुवाहाटी (हिंस)। प्राइड ईस्ट ग्रुप ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य और बाढ़ प्रभावित विद्यालयों के पुनर्वास के उद्देश्य से ऊपरी असम के नाजिरा और डिमौ विधानसभा क्षेत्रों की 20 बाढ़ प्रभावित स्कूलों को कुल एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की सीएमडी तथा मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की अर्धांगिनी रिनिकी भुइयां शर्मा ने नाजिरा विधानसभा क्षेत्र की 15 बाढ़ प्रभावित स्कूलों को पांच-पांच लाख रुपए के चेक प्रदान किए। इसी तरह डिमौ विधानसभा क्षेत्र की पांच बाढ़ प्रभावित स्कूलों को भी पांच-पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इस पहल का उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित विद्यालयों को आवश्यक

सुविधाओं की बहाली में मदद करना और विद्यार्थियों की पढ़ाई को बिना किसी बाधा के जारी रखना है। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री केशव महंत, जल संसाधन मंत्री सुशांत बरगोहाई तथा प्राइड ईस्ट ग्रुप के उपाध्यक्ष (मीडिया) सैयद जारिर हुसैन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कोकराझाड़ में मूगा एवं एरी रेशम उत्पादन की सतत एवं अनुकूलनशील कृषि पद्धतियों पर फील्ड डे कार्यक्रम आयोजित

कोकराझाड़ (विभास)। *मेरा रेशम मेरा अभिमान* 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय रेशम बोर्ड (केरेबो), मूगा एरी रेशमकीट बीज संगठन (मुएरे रेशमकीट बीज संगठन), पी-3 इकाई, कोवाबिल, कोकराझाड़ द्वारा *मूगा एवं एरी रेशम उत्पादन के लिए सतत एवं अनुकूलनशील कृषि पद्धति*या विषय पर एक फील्ड डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक, टिकाऊ एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपनाई जा सकने वाली उन्नत रेशम उत्पादन पद्धतियों के प्रति जागरूक करना तथा खेत स्तर पर नवीन तकनीकों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के दौरान किसानों को मूगा एवं एरी रेशमकीट पालन की वैज्ञानिक पद्धतियों, उन्नत पोषक पौध प्रबंधन, समयबद्ध पौधरोपण एवं छंटाई, स्वस्थ पौध प्रबंधन, रेशमकीट पालन गृह की स्वच्छता एवं विसंक्रमण, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा उन्नत पालन तकनीकों के संबंध में व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। किसानों को रेशमकीटों के स्वस्थ विकास एवं बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित कृषि एवं पालन

पद्धतियों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। बदलती जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मौसम के अनुकूल एवं स्थान-विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। किसानों को स्थानीय संसाधनों का उचित एवं वैज्ञानिक उपयोग करते हुए पर्यावरण-अनुकूल रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, फसल के विभिन्न चरणों में उचित प्रबंधन एवं समय पर तकनीकी हस्तक्षेप के महत्व को समझाया गया। फील्ड डे के दौरान एक अंतरक्रियात्मक तकनीकी सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें किसानों ने मूगा एवं एरी रेशमकीट पालन से संबंधित अपने अनुभव, समस्याएं एवं क्षेत्रीय चुनौतियां साझा कीं। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किसानों के प्रश्नों एवं तकनीकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए आवश्यक तकनीकी सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रदान की गईं। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. सुरक्षा चनोत्रा, वैज्ञानिक-बी, केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी-3 इकाई, कोवाबिल, कोकराझाड़ द्वारा किया गया। श्रीमती कल्पोजिता बसुमतारी ने भी कार्यक्रम के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। यह फील्ड डे एमआरएमए 2.0 के अंतर्गत जमीनी स्तर पर चलाए जा रहे विस्तार एवं जागरूकता कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस प्रकार के किसान-केंद्रित कार्यक्रमों का उद्देश्य वैज्ञानिक रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना, किसान-वैज्ञानिक संपर्क को मजबूत करना, उन्नत एवं सतत तकनीकों को खेत स्तर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा मूगा एवं एरी रेशम उत्पादन से किसानों की आय एवं आजीविका को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम के माध्यम से कोकराझाड़ तथा व्यापक बोड़ोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में मूगा एवं एरी रेशम उत्पादन को अधिक टिकाऊ, उत्पादक एवं बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।

कटक में आयोजित राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता *कलिंग उत्सव 2026* में रंगिया के कलाकारों का शानदार प्रदर्शन

रंगिया (विभास)। ओडिशा के कटक में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की नृत्य प्रतियोगिता *कलिंग उत्सव 2026* में *संदीप कलिता समन्वयी कलाकेंद्र, रंगिया* के बाल कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में संस्थान के छात्रों ने विभिन्न श्रेणियों और अलग-अलग नृत्य शैलियों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई पुरस्कार अपने नाम किए। पुरस्कार जीतने वाले कलाकारों में सीजर भराली, मनस्विनी डी. महंता, रोजलीन रहमान, नताशा कश्यप कलिता, भावना डेका, जोशिता राजबंशी, नवाज रहमान और प्रत्याशा कलिता शामिल हैं। इन सभी बाल कलाकारों ने अपनी कला से निर्णायक मंडलों का दिल जीत लिया और असम का नाम रोशन किया। कार्यक्रम का सफल संयोजन और प्रबंधन बिजय कुमार भराली द्वारा किया गया था। वहीं गुरु बिजय कुमार भराली के कला

और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें समारोह में प्रतिष्ठित *कला वैभव सम्मान* से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के लिए कलाकारों के नृत्य रूपों को बिजय कुमार भराली, रेजआउल रहमान और करबी दास ने तैयार कराया था। पूरे कार्यक्रम का पर्यवेक्षण नवो कुमार बानिया और बिनीता कलिता द्वारा किया गया। रंगिया लौटने पर सभी विजेता कलाकारों और उनके मार्गदर्शकों को स्थानीय निवासियों व कला प्रेमियों द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध मामले में गुजरात पुलिस ने बरपेटा रोड के युवक को किया गिरफ्तार

बरपेटा (हिंस)। देशभर में *डिजिटल अरेस्ट* के नाम पर हो रही साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुजरात पुलिस ने असम के बरपेटा रोड में अभियान चलाकर एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान बरपेटा रोड के नीचुका गांव निवासी रफीकुल आलम के रूप में हुई है। गुजरात पुलिस के पांच सदस्यीय दल ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की। रफीकुल आलम पर गुजरात में एक व्यक्ति को *डिजिटल अरेस्ट* का भय दिखाकर बड़ी रकम ठगने के मामले में शामिल होने का आरोप है। गुजरात पुलिस इस मामले में उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस के अनुसार, *डिजिटल अरेस्ट* साइबर अपराधियों द्वारा अपनाया जाने वाला ठगी का एक तरीका है, जिसमें अपराधी पुलिस, सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं।

रंगिया : बदहाल सड़कों और अधूरे फ्लाईओवर निर्माण को लेकर छात्र संघ ने सौंपा ज्ञापन

रंगिया (विभास)। रंगिया शहर की बदहाल सड़कों और निर्माणाधीन फ्लाईओवरों के बेहद सुस्त काम को लेकर रंगिया आंचलिक छात्र संस्था ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ अपना गुस्सा उजागर किया है। छात्र संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग (सड़क), रंगिया मंडल के कार्यपालक अभियंता को एक ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था में तुरंत सुधार की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में छात्र नेताओं ने कहा है कि मुख्य सड़कों की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इससे आम पैदल यात्रियों, स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं और दैनिक यात्रियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र संघ ने ज्ञापन में मुख्य रूप से दो प्रमुख समस्याओं को उजागर किया है जिसमें एसके-

14 फ्लाईओवर का धीमा काम: निर्माणाधीन एसके-14 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य काफी समय से ठप सा पड़ा है। गति बेहद धीमी होने के कारण रंगिया शहर में रोजाना भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं एसके-12 रेलगेट पर लटकी परियोजना: रेलगेट के ऊपर प्रस्तावित एसके-12 फ्लाईओवर का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इसके चलते रंगिया कॉलेज के विद्यार्थियों, सिविल अस्पताल जाने वाले आपातकालीन मरीजों और स्कूली बच्चों को घंटों बंद रेलगेट पर फंसे रहना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि रंगिया शहर की सभी क्षतिग्रस्त और जर्जर सड़कों की तुरंत मरम्मत कराई जाए और उन्हें पक्का किया जाए। एसके-14 फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित ठेकेदार को कड़े दिशा-निर्देश दिए जाएं।, एसके-12 रेलगेट फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से शुरू कराया जाए। ज्ञापन सौंपते समय रंगिया आंचलिक छात्र संस्था के अध्यक्ष अमिनुल हक और महासचिव अभिजीत कुमार मौजूद रहे। छात्र संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि जनहित और छात्रों के भविष्य को देखते हुए विभाग ने शीघ्र कड़े कदम नहीं उठाए, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

रायमोना और जानालीगांव में एसएसबी ने निकाली *तिरंगा यात्रा*

कोकराझाड़ (विभास)। *हर घर तिरंगा* अभियान के तहत 31वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, गोसाईगांव के तत्वावधान में सोमवार को सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता की अलख जगाते हुए एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा रायमोना से शुरू होकर जानालीगांव तक निकाली गई, जिसमें स्थानीय नागरिकों और युवाओं ने भारी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यह प्रेरणादायक कार्यक्रम 31वीं वाहिनी के कमांडेंट अमित सिंह के कुशल निर्देशन में आयोजित किया गया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व सहायक कमांडेंट नवनीत प्रभाकर ने किया। छात्रों और स्थानीय लोगों ने लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान स्थानीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और युवाओं ने हाथों में तिरंगा थामे पूरे जोश और गर्व के साथ मार्च किया। पूरा क्षेत्र *भारत माता की जय* और *वंदे मातरम्* के नारों से गूंज उठा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों के आम जनमानस में राष्ट्रध्वज

के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय गौरव और आपसी एकता की भावना को और अधिक मजबूत करना था। यात्रा के समापन पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने *हर घर तिरंगा* अभियान के मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने और देश की स्वतंत्रता व अखंडता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। सशस्त्र सीमा बल की 31वीं वाहिनी द्वारा इस प्रकार के जनभागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर देशभक्ति, नागरिक सहभागिता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी स्थानीय लोगों द्वारा भूरी-भूरी प्रशंसा की जा रही है।

संपादकीय

युवाओं का 'नया इंकलाब'

यह 'नया इंकलाब' है, नए युग और नई पीढ़ी का 'इंकलाब' है। यदि ये युवा और छात्र संसद भवन के करीब जा सकते हैं अथवा रांची में विधानसभा भवन के दहलीज पर जाकर बैठ सकते हैं और कुछ युवा विधानसभा भवन के परिसर तक पहुंच सकते हैं, तो ऐ सत्ताधीशो! सावधान, सचेत, सतर्क हो जाओ। यह पीढ़ी कहीं तक भी घुस सकती है! किसी भी सत्ता की चूलें हिला सकती है! कोई अप्रत्याशित घटना सामने आ सकती है! आप चुने हुए मुख्यमंत्री हो या मंत्री अथवा विधायक-सांसद हो, जनता ने ही आपको चुना है, जनता के ही नए प्रतिनिधि आपका निर्वाचन खारिज कर आपको 'सत्ता' से बेदखल कर सकते हैं! झारखंड की राजधानी रांची के युवा, छात्र आंदोलन ने साबित कर दिया है कि कंटीली तारों वाले बैरिकेड्स भी इस पीढ़ी के उग्र कदमों को रोकने में असमर्थ हैं। उन पर पानी की तेज, मोटी बौछार करो, तो ये युवा शैंपो के साथ नहाने लगते हैं, 'होली' का आनंद लूटने लगते हैं, मस्ती में नाचने लगते हैं! पुलिस का खौफ और आंसू गैस के गोलों की चुभन, दहशत और चोट की आशंकाएं सब कुछ 'हवा' हो रहा है। इस पीढ़ी को पुलिसिया लाठियां झेलने का अभ्यास हो गया है। अब एक लाठी शरीर पर पड़ती है, तो ये युवा 'जन गण मन' गाने लगते हैं, लेकिन रांची की जेन जी ने यह भी साबित कर दिया है कि वे 'वर्दी' का सम्मान करेंगे, पुलिसवालों को घेर कर नहीं पीटेंगे, उनके सिरों पर जानलेवा हमले नहीं करेंगे। हालांकि कुछ जूते-चप्पल और पानी की बोतलें रांची आंदोलन में भी पुलिसियों की ओर उछाली गईं। अलबत्ता दिल्ली के जंतर-मंतर और रांची के छात्र आंदोलन में यही बुनियादी, व्यावहारिक और मानसिक फर्क है। रांची के छात्र, युवा आंदोलन की खूबसूरती यह रही है कि जेन जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। एक ही बुनियादी मांग है कि झारखंड लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग में जिस तरह नौकरियों का बाजार सजा है, सरकारी पदों की बाकायदा रेटलिस्ट मौजूद, घोषित है, उसके मद्देनजर सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खुद संज्ञान लेकर इस बाजार और आर्थिक लूटमारी की जांच करना तय किया है। नतीजतन दलालों और भ्रष्टाचारी चेहरों के बैंक खातों, अर्जित आय, लाखों-करोड़ों के लेन-देन, खरीद-फरोख्त के तमाम काले सच सामने आ सकते हैं! शायद मुख्यमंत्री सोरेन इन केंद्रीय जांच एजेंसियों की रणनीति जानते हैं, वह कुछ माह जेल में बिता चुके हैं, लेकिन आंदोलन के मद्देनजर सोरेन सरकार की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। सरकार के 'इकबाल' और उसकी न्यायशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद शिक्षा मंत्री भी हैं, लिहाजा क्या वह सीबीआई जांच में बेनकाब होने से डर रहे हैं? नौकरियों के बाजार में 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की जो रेटलिस्ट सार्वजनिक हुई है, मुख्यमंत्री उस पर स्पष्टीकरण अथवा खंडन जारी क्यों नहीं कर रहे? एक चुनाव जीत कर और मुख्यमंत्री बनकर कोई 'राजा-महाराजा' नहीं बन सकता और जनता को 'कीड़े-मकौड़े' समझने की गलती नहीं कर सकता। इस आंदोलित पीढ़ी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश छोड़ कर भागने को विवश किया है। बेशक भारत में ऐसे उदाहरण नहीं हैं, लेकिन अब देश के विभिन्न हिस्सों में उग्र और गुस्सैल युवा पीढ़ी के आंदोलनों की खबरें आ रही हैं। कल भारत में भी, कुछ भी, अप्रत्याशित और अनहोनी घटनाएं सामने आ सकती हैं। क्या इन हालात को नजरअंदाज किया जा सकता है! रांची में युवा, छात्र सरकार के फैसलों को सतही, दिखावा मान रहे हैं, तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंदोलनकारी युवाओं के पास क्यों नहीं चले जाते? अहंकार किस बात का है। आवास और सिंहासन 'अस्थायी' हैं। विधानसभा भवन तक के मार्च में बिहार, बंगाल से लाए गए, भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे, ऐसे उथले, कुतर्की बयानों से युवाओं का यह 'इंकलाब' अब शांत नहीं किया जा सकता। ये सभी देश के नागरिक और बच्चे हैं, लिहाजा उन्हें दुत्कारा नहीं जा सकता। बेरोजगारी ऐसा विकराल मुद्दा है कि युवा, छात्र इसका समाधान करने वालों को कुछ भी करने की नौबत तक बढ़ सकते हैं! मुख्यमंत्री सोरेन और जिन राज्यों में ऐसे 'इंकलाब' दपदपा रहे हैं, वे होश में आएं और इस जेन जी को न्याय देने की सार्थक कोशिशें करें। युवाओं की मांगों को संबोधित किया जाना चाहिए, यही देश के हित में होगा।

यह पीढ़ी कहीं तक भी घुस सकती है! किसी भी सत्ता की चूलें हिला सकती है! कोई अप्रत्याशित घटना सामने आ सकती है! आप चुने हुए मुख्यमंत्री हो या मंत्री अथवा विधायक-सांसद हो, जनता ने ही आपको चुना है, जनता के ही नए प्रतिनिधि आपका निर्वाचन खारिज कर आपको 'सत्ता' से बेदखल कर सकते हैं! झारखंड की राजधानी रांची के युवा, छात्र आंदोलन ने साबित कर दिया है कि कंटीली तारों वाले बैरिकेड्स भी इस पीढ़ी के उग्र कदमों को रोकने में असमर्थ है। उन पर पानी की तेज, मोटी बौछार करो, तो ये युवा शैंपो के साथ नहाने लगते हैं, 'होली' का आनंद लूटने लगते हैं, मस्ती में नाचने लगते हैं! पुलिस का खौफ और आंसू गैस के गोलों की चुभन, दहशत और चोट की आशंकाएं सब कुछ 'हवा' हो रहा है। इस पीढ़ी को पुलिसिया लाठियां झेलने का अभ्यास हो गया है। अब एक लाठी शरीर पर पड़ती है, तो ये युवा 'जन गण मन' गाने लगते है, लेकिन रांची की जेन जी ने यह भी साबित कर दिया है कि वे 'वर्दी' का सम्मान करेंगे, पुलिसवालों को घेर कर नहीं पीटेंगे, उनके सिरों पर जानलेवा हमले नहीं करेंगे।

फुटपाथ में गड्ढा है और लोग कहते हैं, सावधान रहें

गड्ढों, खुले मैनहोल और टूटी सड़कों के बीच जीवन – नागरिक कब सुरक्षित होंगे?

मृत्यु कब, कहाँ और कैसे आएगी, यह अज्ञात है। हमारे जीवन में, जो सामान्य सी बात लगती है, वैसे ही कई ऐसे खतरे बढ़ते जा रहे हैं जो असाधारण प्रतीत होते हैं। सड़कों पर अनगिनत गड्ढे हैं, सड़कें और गलियाँ उबड़-खाबड़ हैं, नालियाँ खुली नहीं हैं, सीवर के मैनहोल खुले नहीं हैं, कई जगहों पर सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हैं। कुछ इलाकों में स्कूलों की छतें बच्चों पर गिर जाती हैं, तो कुछ इलाकों में अस्पतालों की छतें या स्लैब मरीजों और कर्मचारियों पर गिर जाते हैं। स्कूल बसें पलट जाती हैं, सड़क के विपरीत दिशा से आ रही गाड़ियाँ अचानक मुड़ जाती हैं और गली बच्चों के लिए मौत का जाल बन जाती है, जानवर गली में इधर-उधर घूमते रहते हैं और बुजुर्ग राहगीरों को परेशान करते हैं, और भारी बारिश के बाद बच्चे एक आम सड़क पर फंस जाते हैं और वह मौत का इलाका बन जाती है। रोहतक में लगभग छह इंच बारिश के बाद जलभराव में डूबने से आठ साल के बच्चे की मौत ने एक बार फिर एक चिंताजनक सवाल खड़ा कर दिया है: एक नागरिक के जीवन का क्या मूल्य है? मानसून का मौसम साल में एक बार आता है। हर साल शहरों में जलभराव होता है। जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था, नालियां और सड़कें हर साल समस्या बनी रहती हैं। अधिकारी कहते हैं कि वे तैयार हैं और हर साल सुधार किए जाते हैं। हालांकि, कुछ ही घंटों की बारिश इन दावों की सच्चाई को उजागर करने के लिए काफी होती है, क्योंकि प्रशासन प्रबंधन में विफल रहता है और बारिश का पानी सड़कों पर बह जाता है। यह सिर्फ एक बच्चे की मौत का मामला नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां रोकी जा सकने वाली त्रासदी को अक्सर एक दुर्घटना, एक महज संयोग, भाग्य मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और दोष कहीं और डाल दिया जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां रोकी जा सकने वाली त्रासदी को अक्सर यह एक दुर्घटना थी, यह हमारी गलती नहीं थी, या हम और क्या कर सकते थे? कहकर टाल दिया जाता है। नागरिक बुनियादी ढांचे की विफलता मात्र ही नहीं है, बल्कि यह जिस तरह से विफल हो रहा है वह बेहद चिंताजनक है। बदलाव यह आया है कि नागरिक अब विफलता को स्वाभाविक मान चुके हैं। सड़क में गड्ढा है और लोग कहते हैं कि यह हमेशा से यहीं था। फुटपाथ में गड्ढा है और लोग कहते हैं, सावधान रहें। जलभराव है और लोग कहते हैं, बारिश के बाद ऐसा ही होता है। मवेशी सड़क पर भटक रहे हैं और लोग कहते हैं, कोई क्या कर सकता है? स्कूल की इमारत स्पष्ट रूप से असुरक्षित है और लोग सोचते हैं कि अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह एक सरकारी अस्पताल है जिसकी हालत खराब है और लोग कहते हैं, सरकारी अस्पतालों का यही हाल होता है। यह रवैया खतरनाक है क्योंकि यह सामान्य बात और जीवनशैली बन जाता है। यदि नागरिक जोखिम को अपने जीवन का सामान्य हिस्सा मानने लगें, तो प्रशासन पर सुधार का दबाव भी कम हो जाता है। हमें किसी भी रोकी जा सकने वाली त्रासदी को दुर्घटना मानकर बंद करना होगा। जब कई महीनों से सड़क पर मौजूद गड्ढे के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो सवाल सिर्फ यह नहीं उठता कि क्या हुआ, बल्कि यह भी उठता है कि सड़क पर खतरा क्यों बना रहा? यदि अधिकारियों को खुले मैनहोल की जानकारी है और वे उसे सुरक्षित करने के लिए कदम नहीं उठाते हैं, और कोई बच्चा गड्ढे में गिर जाता है, तो इसे दुर्भाग्य कहना उचित नहीं होगा। स्कूल भवन का अनावश्यक रूप से गिर जाना सिर्फ एक बुरी घटना नहीं मानी जानी चाहिए। यह बात अस्पताल की सुरक्षा, स्कूल बसों की स्थिति, पुलों के रखरखाव, जल निकासी व्यवस्था और सड़क की गुणवत्ता के साथ-साथ स्कूलों में आवारा पशुओं के नियंत्रण पर भी लागू होती है। ये प्रशासनिक मामले नहीं हैं, बल्कि ये जन सुरक्षा और लोगों के जीवन से जुड़े मामले हैं। लेकिन हमारे सार्वजनिक विमर्श की त्रासदी यह है कि हम बार-बार इन वास्तविक प्रश्नों से मुंह मोड़ लेते हैं। धार्मिक संदर्भ वाला कोई भी बयान समाज में आक्रोश पैदा कर सकता है। इसका परिणाम हजारों सोशल मीडिया पोस्ट, घंटों टीवी स्टूडियो बहस और राजनीतिक बयानबाजी के रूप में सामने आता है। आहत भावनाओं, पहचान और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। हालांकि, ऐसे बच्चे की मौत के लिए जवाबदेही को लेकर जनता का निरंतर आक्रोश गायब है। क्यों? क्या धार्मिक विवाद होने पर एक आम आदमी के जीवन का महत्व कम हो जाता है? क्या खुले सीवर में बच्चे का डूबना स्थानीय खबर है? क्या किसी असुरक्षित सड़क पर किसान, मजदूर, बुजुर्ग या छात्र की मौत महज दुर्भाग्य की बात है? क्या ऐसा लगता है कि सरकार से जवाब मांगने के मामले में देश को चुनौती देना उनकी मांगों का जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा है? बिलकुल नहीं। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। लोग कर अदा करते हैं और सुरक्षित सड़कें, स्वच्छ शहर, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित स्कूल, प्रभावी परिवहन और बुनियादी नागरिक अवसंरचना की अपेक्षा रखते हैं। ये विलासिता नहीं हैं। ये गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत कारक हैं। देशभक्ति सरकार की किसी भी गलती को छुपाने का बहाना नहीं है। राष्ट्रवाद का अर्थ यह नहीं है कि देश की कमियों को उजागर करने वाले सभी लोगों को राष्ट्र-विरोधी करार दिया जाए। एक जिम्मेदार नागरिक वह है जो देश की प्रगति देखना चाहता है और इसलिए कठिन प्रश्न उठाता है। टूटी हुई सड़क की मरम्मत की मांग न करना राष्ट्र-विरोधी नहीं है। असुरक्षित स्कूल को सुरक्षित बनाने की मांग करना राष्ट्र का अपमान नहीं है। अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल न उठाना व्यवस्था विरोधी नहीं है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की कोई भी आलोचना विदेशी साजिश का सबूत नहीं है। दुर्भाग्य से, नागरिक मामलों से जुड़े गंभीर मुद्दे राजनीतिक खेमों में बँटते जा रहे हैं। सरकार की प्रशंसा को देशभक्ति कहा जाता है और किसी भी आलोचना को विपक्ष या नकारात्मक आवाज़ करार दिया जाता है। नकारात्मकता लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि इससे आलोचना और जवाबदेही की कमी पैदा होती है, जो सुशासन के लिए आवश्यक तत्व हैं। मीडिया की भी इसमें बड़ी भूमिका है। यह केवल सफलताओं का जश्न मनाने का मंच नहीं है, बल्कि इसे उन क्षेत्रों की भी पड़ताल करनी चाहिए जिनमें सरकारी कुप्रबंधन के कारण आम नागरिक पीड़ित हैं। हम सभी जानते हैं कि टेलीविजन चैनल राजनीतिक बहसों पर कितना समय देते हैं, वे सड़क सुरक्षा, जल निकासी व्यवस्था की विफलता, स्कूल के बुनियादी ढांचे, अस्पताल भवनों और नागरिक सेवाओं जैसी अन्य चीजों पर भी सार्थक समय दे सकते हैं। किसी शहर का असली स्वरूप विज्ञापनों या आधिकारिक बयानों में नहीं दिखता। बारिश होने पर यह उसकी सड़कों पर नज़र आता है। केवल भवन निर्माण ही विकास नहीं है। रखरखाव भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़क निर्माण ही पर्याप्त नहीं है; सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। पुल का निर्माण ही काफी नहीं है; नियमित निरीक्षण भी जरूरी है। नाली का निर्माण महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी सफाई और सुरक्षा भी आवश्यक है। स्कूलों का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है; स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है। हम दुर्घटनाओं को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन लापरवाही के कारण होने वाली कई त्रासदियों को टाला जा सकता है। इसके लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है। सड़क की मरम्मत आखिरी बार कब हुई थी? गड्ढा कब बना था? मैनहोल खुला क्यों था? जल निकासी व्यवस्था में खराबी का क्या कारण था।

स्कूल बसें पलट जाती है, सड़क के विपरीत दिशा से आ रही गाड़ियां अचानक मुड़ जाती हैं और गली बच्चों के लिए मौत का जाल बन जाती है, जानवर गली में इधर-उधर घूमते रहते हैं और बुजुर्ग राहगीरों को परेशान करते हैं, और भारी बारिश के बाद बच्चे एक आम सड़क पर फंस जाते हैं और वह मौत का इलाका बन जाती है। रोहतक में लगभग छह इंच बारिश के बाद जलभराव में डूबने से आठ साल के बच्चे की मौत ने एक बार फिर एक चिंताजनक सवाल खड़ा कर दिया है: एक नागरिक के जीवन का क्या मूल्य है? मानसून का मौसम साल में एक बार आता है। हर साल शहरों में जलभराव होता है। जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था, नालियां और सड़कें हर साल समस्या बनी रहती हैं। अधिकारी कहते हैं कि वे तैयार हैं और हर साल सुधार किए जाते हैं। हालांकि, कुछ ही घंटों की बारिश इन दावों की सच्चाई को उजागर करने के लिए काफी होती है, क्योंकि प्रशासन प्रबंधन में विफल रहता है और बारिश का पानी सड़कों पर बह जाता है।

कुछ अलग

जीवन को समझने का अर्थ है उसके साथ संवाद

तर्क ने मनुष्य को अंधविश्वासों से लड़ना सिखाया, प्रकृति के रहस्यों को समझने का साहस व विवेक दिया तथा विज्ञान, गणित एवं दर्शन की महान परंपराओं को जन्म दिया और विकसित किया। किंतु, जब मनुष्य यह मान बैठता है कि तर्क ही संपूर्ण सत्य है, तब वह जीवन के एक बड़े हिस्से की अनदेखी कर देता है। जीवन किसी गणितीय समीकरण की तरह नहीं है, जहां हर सवाल का एक निश्चित जवाब मौजूद हो। जीवन तो एक कविता की तरह है, जिसमें अर्थ शब्दों के बीच के मौन में भी छिपा होता है। यदि आप केवल तर्क से जीवन को पढ़ेंगे, तो आपको उसका व्याकरण तो मिल जाएगा, पर उसकी धड़कन नहीं मिल पाएगी। तर्क हमें बताता है कि फूल कैसे खिलता है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि एक खिला हुआ फूल देखकर हृदय क्यों भर आता है। विज्ञान प्रकाश की तरंग-लंबाई के बारे में तो समझा सकता है, पर सूर्यास्त की सुंदरता का अनुभव नहीं दे सकता। मनुष्य का जीवन तर्क, भावना, कल्पना, स्मृति और मौन का मिलाजुला संगीत है। यदि इनमें से किसी एक को ही सत्य घोषित कर दिया जाए, तो संगीत टूट जाता है। भारत की यात्रा करते हुए मैंने देखा कि यहां लोग मौन को भी संवाद मानते हैं। एक साधु घंटों बिना कुछ बोले बैठ सकता है और फिर भी उसके आसपास मौजूद लोग अनुभव करते हैं कि उनसे कुछ कहा गया है। तर्क मनुष्य को दिशा देता है, किंतु अनुभव उसे गहराई देता है। दिशा बिना गहराई के मनुष्य को यांत्रिक बना देती है, गहराई बिना दिशा के उसे भटका सकती है। जीवन का सौंदर्य इन दोनों के संतुलन में ही है। हम नश्वर हैं, फिर भी अमरता का स्वप्न देखते हैं। हम अकेले जन्म लेते हैं, फिर भी संबंधों के बिना जी नहीं सकते।

देश दुनीया से

वन अधिकार कानून को कमजोर करने के प्रयास

भारतवर्ष में वन हमेशा आदिवासी समुदायों और कृषि-पशुपालन-दस्तकारी व्यवसाय से जुड़े समाजों के लिए आजीविका के आधार रहे हैं, जिसमें चरागाह भूमियों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसे चरागाह दख़तान, चरागाह बिला दख़तान, गोचर भूमि आदि नामों से जाना जाता था। अंग्रेजों ने जब 1860 के आसपास वन भूमियों पर कब्जा करके वनों को वन विभाग के हवाले करने का कार्य आरंभ किया, तब वनों का चरित्र और प्रबन्धन पूरी तरह से बदल गया। अब वनों का मालिक वन विभाग हो गया और स्थानीय समुदाय कुछ सीमित स्तर के बरतनदार मात्र बना दिए गए, जिन्हें वन विभाग की दया पर निर्भर कर दिया गया। आदिवासी इलाकों में इस स्थिति के खिलाफ कई आंदोलन और लड़ाइयां हुईं, किन्तु अन्ततोगत्वा ब्रिटिश वन प्रबन्धन का युग शुरू हुआ जिसमें वन विभाग का लक्ष्य वनों के व्यापार से अधिक से अधिक कमाई करके ब्रिटिश सरकार के हवाले करना था। इस वजह से वनों के स्वरूप को भी बदलने का काम शुरू हुआ। मिश्रित बहुउपयोगी वनों को एकल प्रजाति के व्यापारिक प्रजाति के वनों में बदला जाने लगा जिससे स्थनीय समाजों की वनों पर आधारित आजीविकाएं नष्ट होती चली गईं। यह क्रम चिपको आन्दोलन द्वारा इस व्यापारिक वन प्रबन्धन के खिलाफ 70-80 के दशक में किए गए लंबे संघर्ष तक आजादी के बाद भी जारी रहा। हालांकि 1986 की वन नीति के बाद से वन रोपण नीतियों में बदलाव आने लगा, किन्तु आदिवासियों और अन्य वन निर्भर समुदायों को डेढ़ सदी तक हुई हानि को देखते हुए 2006 में वन अधिकार कानून बना कर इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का प्रयास हुआ, जिसके अनुसार वन भूमि में खेती करने वाले आदिवासी और अन्य वन निर्भर समुदायों को खेती योग्य भूमि कानूनी तौर पर उन्हें देने, वनों में उनके बरतनदारी अधिकारों को कानूनी अधिकार में बदलने और बरतनदारी वन क्षेत्रों को इन समुदायों को अपनी जरूरतों के अनुसार प्रबंधित करने के प्रावधान किए गए। इस कानून को विशेष कानून का दर्जा दिया गया, ताकि यह अन्य सभी वन कानूनों की परवाह किए बिना लागू किया जा सके। वन भूमि पर इस तरह समुदायों के बढ़ते दखल और अधिकारों के मद्देनजर वन विभाग शुरू से ही इसके विरोध में बना रहा। इसी खतरे को भांपते हुए इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी आदिवासी या जनजातीय मंत्रालय को सौंपी गई। अन्य प्रशासनिक स्तरों के परोक्ष विरोध और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में 2008 में अधिसूचित हो जाने के बावजूद यह कानून कछुआ चाल से ही लागू किया जा रहा है। धीरे धीरे वन अधिकार कानून के अंतर्गत बनाई गई ग्राम सभाओं की शक्तियां जिला स्तरीय अनुश्रवण समितियों को सामुदायिक वन प्रबंधन में व्यापक भूमिका देकर कम की जा रही हैं। सामुदायिक वनों पर सामूहिक स्वामित्व आधारित व्यवस्था को सांझे वन प्रबंधन की दिशा में मोड़ा जा रहा है। सांझा वन प्रबन्धन अपनी सीमाओं के चलते कोई प्रभावी सफलता दिखाने में पहले ही असफल हो चुका है, क्योंकि उसमें समुदाय की भूमिका नाममात्र की थी। जब तक समुदाय को यह विश्वास नहीं हो जाता कि यह वन हमारा है और हमें मिलकर इसकी रक्षा और संवर्धन करना है और इसके लाभ भी प्राप्त करने हैं, तब तक समुदाय को सक्रिय प्रबंधक नहीं बनाया जा सकता। इसी कमी को वन अधिकार कानून ध्यान में रखता है और अधिकार आधारित व्यवस्था बनाता है। 27 जुलाई 2026 को पर्यावरण और वन मंत्रालय और आदिवासी मंत्रालय का एक सांझा पत्र जारी किया गया है, जिसमें सांझा वन प्रबंधन की बात की गई है और 2023 के वर्किंग प्लान कोड के अनुसार सामुदायिक वनों के प्रबंधन की कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया है, और वन विभाग के सहयोग से यह योजना बनाई जाएगी। जाहिर है कि इसमें समुदायों की बात तो हाशिए पर ही रहेगी। यह कोड इतना पेचीदा है कि कोई भी सामुदायिक वन प्रबंधन समिति इस आधार पर योजना बना ही नहीं सकती है। गोचर भूमियों के बारे में तो कोई स्पष्ट जिक्र तक इस कोड में नहीं है। लोगों की नजर में वन विभाग की भूमिका हमेशा अधिकार हड़पने की रही है तो इस प्रक्रिया में उनका विश्वास करना थोड़ा कठिन हो रहा है। जैसे अन्य विभागों में होता है कि जमीन तो लोगों की है, कृषि विभाग उसमें जरूरी सहयोग करता है, उद्योग तो उद्योपति का है, उद्योग विभाग उसमें जरूरी आर्थिक सुविधाएं और सहयोग देता है, इसी तरह सामुदायिक वन जो वन अधिकार कानून के तहत समुदाय को दिया गया उसका मालिक तो समुदाय है, वन विभाग को उसमें केवल जरूरत पडने पर मांगा गया सहयोग देने तक सीमित रखना चाहिए। तभी अधिकार आधारित व्यवस्था कायम हो सकेगी। हालांकि इस पूरी व्यवस्था को वन अधिकार कानून की धारणा के अनुसार विकसित होने में कुछ समय लगेगा। इसमें, करते हुए सीखने, की प्रक्रिया को अपनाना होगा। किन्तु सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखनी होगी, वह है कि कहीं भी समुदाय को यह नहीं लगना चाहिए कि हमारी स्थिति इस व्यवस्था में भी बाहरी तमाशाई से ज्यादा नहीं है। इसे वन अधिकार कानून की आत्मा पर ही आघात लगेगा और वांछित प्रतिफल भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

आप का नजरीया

बरसाती परिवहन की चौकसी

बरसात के महीनों में भयभीत हिमाचल। खोखली पहाडियां, संकरे रास्ते, परिवहन के निरंकुश इरादे और सडक़ों पर बढ़ता दबाव दुर्घटनाओं के आंकड़ों में मातम की व्यथा बन जाता है। इस बार चुराह दुर्घटना ने पूरे परिदृश्य को सोचने पर विवश किया है, तो पहाड़ से गिरती चट्टानों ने पूरे प्रदेश में मकबरे सजा दिए हैं। पत्थरों की बरसात ने परिवहन को जोखिम भरा बना दिया है। सडक़ दुर्घटनाओं में पर्यटक दुर्घटनाएं शामिल कर लें, तो बरसात के पंजे खतरनाक साबित हो रहे हैं। चुराह में वाहनों का संचालन सडक़ों की स्थिति की शिकायत करता है, लेकिन जीवन की आवश्यकताएं और सियासत की फरमाइश में नक्शे अक्सर नहीं देखे जाते। प्रदेश की आरंभिक बरसात ने डेढ़ सौ के करीब रास्ते बंद रखे हैं, तो अंदरूनी घाटियों के सफर की कहानी मुश्किल है। पर्यटक या धार्मिक स्थलों में कितना पर्यटन-कितना जोखिम मोल लेने का साहस। विडंबना यह है कि पर्यटक स्थलों की सडक़ें टूटी अवस्था में वाहनों के भारी दबाव कब तक सहेंगी। इतना ही नहीं, सडक़ों के किनारे जल निकासी का इंतजाम जहां नहीं है, वहां काल बह रहा है या रास्तों को विकराल बना रहा है। किन्नौर-कैलाश यात्रा या आगे मणिमहेश के दर्शनों की बारात जब निकलेगी तो सडक़ पर पहिए खूंखार हो सकते हैं। ऐसे में बरसात में कितनी यात्रा, कितना सफर जरूरी, इसके ऊपर मंथन करना होगा। हिमाचल में तीर्थ यात्राओं का माध्यम बन रहे दोपहिया वाहन, परिवहन नियमों का सीधा उल्लंघन हैं। अभी जो तीर्थ यात्री प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, उनके सुरक्षा के इंतजाम इतने नर्म क्यों कि लोग बिना हेल्मेट, ऊंचे झंडे तथा म्युजिक सिस्टम के साथ रास्तों पर निरंकुश दौड़ रहे हैं। ऐसे में बरसाती परिवहन की चौकसी मुकर्रर करते हुए वाहन चालकों को खतरे के खिलाड़ी बनने से रोकना होगा। पर्यटन और परिवहन के रिश्तों में सुरक्षित मानदंड अपनाने की निगरानी जरूरी है, जबकि सडक़ों का ऑडिट सुनिश्चित करना होगा। धर्मशाला से मकलोडगंज के तमाम रास्ते अगर खंडहर हैं, तो डेस्टिनेशन टूरिस्ट के जीवन से खेलने की छूट क्यों। कुछ इसी तरह फोरलेन निर्माण की साइट्स पर अंधे कदम फरिश्ते नहीं हो सकते। बावजूद इसके कि सडक़ें चौड़ी हो रही हैं और फोरलेन निर्माण चल रहा है, हिमाचल की सडक़ों पर मौत का आखेट भी चल रहा है। ऊना के पीरनिगाह तक अगर श्रद्धालू ट्रैक्टर ट्रॉली में आएंगे, तो यह कौनसी अनुमति जो सरेआम दुर्घटना का पुलिंदा बन जाती है। ऐसे में परिवहन खास तौर पर बरसाती परिवहन में भागते-दौड़ते मंजर को संयमित करने की जरूरत है, जबकि बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं को परिवहन के मानकों तथा कायदे-कानून के तहत चलना सिखाना पड़ेगा। सडक़ निर्माण की वर्तमान तकनीक खतरे बढ़ा रही है या लापरवाही बढ़ रही है। दुर्घटनाओं में मानवीय चूक सब पर भारी पड़ती है, लेकिन सडक़ों की देखभाल तथा उच्च मानदंडों के अनुरूप रखरखाव में आ रही कमी के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। बहुत सारे बस रूट अगर जोखिम में चल रहे हैं, तो उन्हें बंद कर देना होगा। प्रदेश सरकार को पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों में ग्रीन टैक्स लगा कर परिवहन और पार्किंग की दिशा में नए प्रयत्न करने चाहिएं। मसलन धर्मशाला से मकलोडगंज की ओर ग्रीन टैक्स लगाया जाए, तो इस आय से सडक़ निर्माण के मानदंड ऊंचे होंगे तथा पार्किंग सुविधा में विकास होगा। बीड़ से बिलिंग ग्रीन टैक्स से सडक़ को पूरी तरह विकसित किया जा सकता है। बरसाती दिक्कतों से रूबरू हिमाचल को अधोसंरचना में गुणवत्ता के नए पहलू जोडने चाहिएं, मसलन पर्वतीय अंचल की सडक़ों को एलिवेटिड रोड की परिभाषा में सशक्त किया जा सकता है।

पत्थरों की बरसात ने परिवहन को जोखिम भरा बना दिया है। सडक़ दुर्घटनाओं में पर्यटक दुर्घटनाएं शामिल कर लें, तो बरसात के पंजे खतरनाक साबित हो रहे हैं। चुराह में वाहनों का संचालन सडक़ों की स्थिति की शिकायत करता है, लेकिन जीवन की आवश्यकताएं और सियासत की फरमाइश में नक्शे अक्सर नहीं देखे जाते। प्रदेश की आरंभिक बरसात ने डेढ़ सौ के करीब रास्ते बंद रखे हैं, तो अंदरूनी घाटियों के सफर की कहानी मुश्किल है। पर्यटक या धार्मिक स्थलों में कितना पर्यटन-कितना जोखिम मोल लेने का साहस। विडंबना यह है कि पर्यटक स्थलों की सडक़ें टूटी अवस्था में वाहनों के भारी दबाव कब तक सहेंगी। इतना ही नहीं, सडक़ों के किनारे जल निकासी का इंतजाम जहां नहीं है, वहां काल बह रहा है या रास्तों को विकराल बना रहा है। किन्नौर-कैलाश यात्रा या आगे मणिमहेश के दर्शनों की बारात जब निकलेगी तो सडक़ पर पहिए खूंखार हो सकते हैं। ऐसे में बरसात में कितनी यात्रा, कितना सफर जरूरी, इसके ऊपर मंथन करना होगा। हिमाचल में तीर्थ यात्राओं का माध्यम बन रहे दोपहिया वाहन, परिवहन नियमों का सीधा उल्लंघन हैं। अभी जो तीर्थ यात्री प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, उनके सुरक्षा के इंतजाम इतने नर्म क्यों कि लोग बिना हेल्मेट, ऊंचे झंडे तथा म्युजिक सिस्टम के साथ रास्तों पर निरंकुश दौड़ रहे हैं। ऐसे में बरसाती परिवहन की चौकसी मुकर्रर करते हुए वाहन चालकों को खतरे के खिलाड़ी बनने से रोकना होगा। पर्यटन और परिवहन के रिश्तों में सुरक्षित मानदंड अपनाने की निगरानी जरूरी है, जबकि सडक़ों का ऑडिट सुनिश्चित करना होगा।

दृष्टि कोण

बुजुर्ग मां-बाप को बोझ न समझें युवा

बुजुर्गों खास तौर पर मां-बाप के प्रति संवेदनहीनता की एक घटना सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है और लोग इसे बच्चों और मां-बाप के रिश्तों में आती कड़वाहट और आधुनिक समाज की संवेदनहीनता के उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। यह मामला हरियाणा के सोनीपत में स्थित एक वृद्धाश्रम से जुड़ा है जहां शिवचरण गुप्ता नाम के एक बुजुर्ग की मृत्यु के बाद उनकी बेटियों ने आने के बजाय 5100 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार देखने को कहा। कारोबार में करोड़ों के घाटे के बाद, शिवचरण गुप्ता करीब डेढ़ साल से अपनी पत्नी के साथ सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। बुजुर्ग की तीन बेटियां हैं। पिता के निधन के बाद जब वृद्धाश्रम संचालकों ने उनसे संपर्क किया, तो वे अंतिम विदाई के लिए खुद नहीं आईं। इस असंवेदनशील व्यवहार से आहत होकर वृद्धाश्रम प्रबंधन ने बेटियों द्वारा भेजे गए 5100 रुपए को वापस लौटा दिया और खुद अपने खर्च पर बुजुर्ग का सम्मानजनक अंतिम संस्कार संपन्न कराया। आखिर समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? यह एक कड़वा सामाजिक सच है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ लोग वृद्ध माता-पिता को बोझ मानने लगे हैं, लेकिन नैतिक, मानवीय और सांस्कृतिक रूप से यह पूरी तरह गलत है। आज की युवा पीढ़ी पर अपने बच्चों और करियर का इतना दबाव होता है कि वे बुजुर्गों को समय नहीं दे पाते। कई बार बच्चों में नैतिक मूल्यों और बड़ों के प्रति आदर की कमी हो जाती है। मां-बाप ने बिना किसी स्वार्थ के हमें चलना, बोलना और जीना सिखाया है। जब माता-पिता को सबसे ज्यादा प्यार और सहारे की जरूरत होती है, तब उनका साथ देना हर संतान का पहला धर्म होना चाहिए। माता-पिता बोझ नहीं, बल्कि घर की छांव और अनुभव की पूंजी होते हैं। जब बच्चे अपने माता-पिता को बोझ समझने लगते हैं, तो यह उस रिश्ते की पवित्रता पर एक गहरा आघात है। बढ़ता एकल परिवार, महिलाओं द्वारा धन अर्जन में प्रत्यक्ष भागीदारी, अच्छे संस्कारों का अभाव, बुजुर्गों द्वारा अपने जीवनकाल में अपने स्वास्थ्य से अधिक दूसरे कार्यों को महत्व देना, बुजुर्गों द्वारा अपने यौवनकाल में अपने बुजुर्गों की खुशी से समुचित देखभाल न करना, भौतिक उपलब्धियों को ही एकमात्र जीवन में सफलता समझना, दोहरे मापदंड, हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अत्यधिक प्रतियोगिता होना, असंतुष्ट मानव स्वभाव हमारी संस्कृति पर आघात है। आज के बच्चे तर्क देते हुए कहते हैं कि घर चलाने के लिए धन कमाने के काम में लंबा समय व्यतीत करने के बाद इतनी ऊर्जा नहीं रहती कि घर की दूसरी जिम्मेदारियों को भी खुशी से पूरा किया जाए। माता-पिता हर मुश्किल के बीच अपनी संतान को बहुत प्यार से पालते हैं, जबकि आज की संतान ऐसा खुशी से नहीं कर पाती। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि 21वीं सदी में सामाजिक रिश्ते काफी दबाव से गुजर रहे हैं। लेकिन निराशाजनक बात यह है कि माता-पिता और बच्चे का पवित्र रिश्ता उथल-पुथल का शिकार हो गया है और आज कई बच्चे अपने बूढ़े माता-पिता को बोझ समझते हैं। बच्चों के लिए उनके माता-पिता आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बोझ बन जाते हैं। आज के बच्चे बेहद कैरियर उन्मुख लोग हैं। वे अपने कार्यालयों में या क्लबों और सामाजिक समारोहों के माध्यम से व्यावसायिक संबंध बनाए रखने में बहुत समय बिताते हैं। बाजार में मौजूद गलाकाट प्रतिस्पर्धा को देखते हुए आज की कार्य संस्कृति अत्यधिक मांग वाली है। यह तनाव उन्हें अपने जीवनसाथी या बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने नहीं देता। अपने माता-पिता की बढ़ती उम्र की समस्याओं के कारण, बच्चे अपने कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां महसूस करते हैं। इस पीढ़ी के बच्चों के साथ एक और बड़ी समस्या यह भी है कि वे अपनी सफलता को बढ़ावा देते हैं और खुद को अपनी स्थिति का निर्माता मानते हैं।

हरियाणा में बढ़ रहे हैं दलित उत्पीड़न की घटनाओं के अदालती केस

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा में अनुसूचित जाति-जनजाति के खिलाफ अत्याचार से संबंधित अदालती मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। दलितों को अदालतों से केवल तारीख मिल रही है। 2022 में ऐसे 1633 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में घटकर 1077 रह गए। इसके बावजूद लंबित मामलों की संख्या 3119 से बढ़कर 3910 हो गई। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल के लोकसभा में सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने यह आंकड़े दिए। 2024 में दर्ज 1077 मामलों में 661 में आरोपपत्र दाखिल हुआ, जबकि सिर्फ 56 मामलों में दोषसिद्धि हुई। साल के अंत तक 3910 मामले लंबित थे। यानी नए मामलों में कमी के बावजूद पुराने मामलों के निपटारे की रफ्तार लंबित बोझ कम करने के लिए पर्याप्त नहीं रही। 2022 से 2024 के बीच नए मामलों की संख्या 1633 से घटकर 1077 हुई यानी करीब 34 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इसके उलट लंबित मामलों की संख्या 3119 से बढ़कर 3910 हो गई। करीब 25 फीसदी की बढ़ोतरी इस अवधि में हुई। 2023 में 1539 नए मामले दर्ज हुए थे और साल के अंत में 3569 मामले लंबित थे।

योगी सरकार का भूमाफियाओं पर प्रहार, अवैध कब्जे से मुक्त कराई दो लाख एकड़ जमीन

एंटी भूमाफिया पोर्टल से ऑनलाइन शिकायतों की निगरानी, 99 प्रतिशत का हुआ निस्तारण

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का एंटी भूमाफिया अभियान लगातार चर्चा में रहा है। राजस्व विभाग के मुताबिक सख्त कार्रवाई और विभिन्न अभियान के तहत बीते साढ़े नौ साल में प्रदेश में 84,005 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। यह क्षेत्रफल लगभग 2.08 लाख एकड़ के बराबर है। भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के साथ शिकायतों के निस्तारण, मुकदमों की पैरवी और चिह्नित भूमाफियाओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई ने इस अभियान को और व्यापक रूप दिया। बीते वर्षों में इन कार्रवाइयों ने भूमाफियों के खिलाफ योगी सरकार ने अपनी मंशा साफ जाहिर की है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में सार्वजनिक संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए चार स्तरीय-राज्य, मंडल, जनपद और तहसील स्तर पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका उद्देश्य अवैध कब्जों की पहचान से लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने तक

की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना है। इसके तहत अवैध कब्जों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने और की गई कार्रवाई की प्रभावी निगरानी के लिए एंटी भू-माफिया पोर्टल विकसित किया गया। राज्य में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित कुल 4,34,016 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 4,31,697 शिकायतों यानी 99 प्रतिशत से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं 2,319 शिकायतें निस्तारण के लिए लंबित हैं। योगी सरकार में विभान ने अभियान के जरिए सिर्फ जमीन को कब्जामुक्त कराने पर ही जोर नहीं दिया गया, बल्कि शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने से लेकर उनके निस्तारण तक निगरानी की व्यवस्था भी बनाई गई है। इससे कार्रवाई की स्थिति को लगातार ट्रैक करने का तंत्र विकसित हुआ। उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में 84,005 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना है। इससे प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए लगभग 2.08 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध हो गई है। इसमें बड़े स्तर पर सरकारी लैंडबैंक भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न विकास योजनाओं के लिए किया जाना संभव होगा। एंटी भू-माफिया पोर्टल अभियान की निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम बना है। अवैध कब्जों के मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया। गत वर्षों में अभियानों के तहत 25,068 राजस्व वाद, 1,168 सिविल वाद और 4,751 एफआईआर दर्ज कराई गईं। वहीं अभियान के तहत 1,413 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिह्नित किया गया। इनमें से वर्तमान में 144 भू-माफिया जेल में बंद हैं। राजस्व विभाग के मुताबिक 1,621 अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत 1,621 मामले, 109 लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 के खिलाफ, गैंगस्टर एक्ट के तहत 70 लोगों, गुंडा एक्ट के तहत 206 लोगों व अन्य धाराओं के तहत 1,745 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन को योगी सरकार लैंडबैंक के रूप में विकसित कर औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार का आधार बनाती आ रही है। अब खाली कराई गई भूमि को व्यवस्थित तरीके से चिन्हित कर उद्योगों, फार्मास्युटिकल और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों, लॉजिस्टिक पार्क, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज व अन्य बड़े निवेश प्रस्तावों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने में तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राजस्व विभाग के प्रदेशव्यापी अभियान ने योगी सरकार के विकास से जुड़े विजन को और मजबूती प्रदान करने का काम किया है।

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जुलाई माह में रिश्वत लेते 14 व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जुलाई 2026 के दौरान भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 अलग-अलग ट्रैप मामलों में 12 सरकारी कर्मचारियों और 2 निजी व्यक्तियों सहित कुल 14 व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के सरकारी कामकाज में भ्रष्ट गतिविधियों को बढ़ावा देने अथवा उनमें संलिप्त होने वाले मामलों पर भी विजिलेंस ब्यूरो की कड़ी नजर है। प्रवक्ता ने बताया कि जुलाई महीने के दौरान ब्यूरो ने विभिन्न सक्षम अदालतों में 16 विजिलेंस मामलों से संबंधित चालान पेश किए हैं। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा आरोपियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे बताया कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की गहन जांच के लिए जुलाई के दौरान 2 विजिलेंस जांच दर्ज की गई हैं।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की पहल : अब एआई बताएगा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य के नए मॉडल

जयपुर (हिंस)। आयुर्वेद की पारंपरिक ज्ञान परंपरा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और आधुनिक डिजिटल तकनीक से जोड़ने की दिशा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर ने महत्वपूर्ण पहल की है। जोरावर सिंह गेट स्थित संस्थान और नोएडा की वेलविज इनोवेशन के बीच आयुर्वेद, एआई, डिजिटल तकनीक, डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाओं और स्कूल वेलनेस के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का उद्देश्य आयुर्वेद के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान, एआई और डिजिटल तकनीक के साथ जोड़कर निवारक एवं स्वास्थ्य संवर्धन आधारित चिकित्सा के नए मॉडल विकसित करना है। इसके तहत एआई और डेटा आधारित तकनीकों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं वेलनेस से जुड़े विभिन्न मानकों के आकलन, विश्लेषण और अध्ययन को मजबूत किया जाएगा। साथ ही आयुर्वेद के प्रासंगिक सिद्धांतों को आधुनिक डिजिटल फ्रेमवर्क से जोड़ने पर काम होगा। एमओयू के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के साथ क्षमता निर्माण, ज्ञान एवं विशेषज्ञता के आदान-प्रदान, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेद एवं डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा। स्कूल वेलनेस को भी समझौते में प्रमुख क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। इसके तहत बच्चों और

युवाओं के लिए आयुर्वेद आधारित स्वस्थ जीवनशैली तथा निवारक स्वास्थ्य से जुड़े नए मॉडल विकसित किए जाएंगे। इससे कम उम्र से ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। एमओयू के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा, कुलसचिव प्रो. अनिता शर्मा, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभागाध्यक्ष प्रो. अनुपम श्रीवास्तव तथा उपनिदेशक (प्रशासन) चंद्रशेखर शर्मा मौजूद रहे। वेलविज इनोवेशन की ओर से डायरेक्टर ऑपरेशंस पुनीता बंसल, डॉ. दिव्या शारद और सोहेल शेख ने सहभागिता की। इस पहल से आयुर्वेद और आधुनिक तकनीक के बीच समन्वय बढ़ने के साथ डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाओं, शोध और निवारक चिकित्सा के क्षेत्र में नए प्रयोगों की संभावनाएं मजबूत होंगी।

सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर विवाद, वन मंत्री संजय शर्मा निगम में धरने पर बैठ बोले, कलेक्टर रहने लायक नहीं

अलवर (हिंस)। नगर निगम अलवर में वर्ष 2012 में हुई सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों के समर्थन में राजस्थान के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा बुधवार सुबह नगर निगम पहुंचे और कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ गए। मंत्री ने जिला प्रशासन और नगर निगम आयुक्त की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार और विभाग के स्तर से नियुक्ति को लेकर निर्देश हैं तो कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2012 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। उनके अनुसार 329 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए, जिसके बाद कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए। मंत्री का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आने के बावजूद करीब सवा साल बीत जाने पर भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए हैं। संजय शर्मा के मुताबिक इस मामले में लंबे समय से डीएलबी और नगर निगम के बीच पत्राचार चल रहा है। उन्होंने

आरोप लगाया कि पिछले चार-पांच महीनों से तत्कालीन आयुक्त की ओर से शासन विभाग को सही स्थिति से अवगत नहीं कराया गया। मंत्री ने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर से इस मामले में बातचीत की। कलेक्टर की ओर से 69 कर्मचारियों को पात्र बताए जाने की बात कही। वहीं, मंत्री के अनुसार डीएलबी की ओर से 369 कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कही जा रही है। इसी अंतर को लेकर वन मंत्री ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले करीब सात महीनों से उन्हें और संभवत: संबंधित शासन विभाग के मंत्री को भी इस मामले में गुमराह किया जा रहा है। धरने के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि सरकार के स्तर पर नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश हैं तो अधिकारियों को उसका पालन करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कलेक्टर और आयुक्त सरकार से बड़े हो गए हैं? मंत्री ने कलेक्टर की कार्यशैली पर भी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि यदि अधिकारी सरकार के निर्देशों के बावजूद काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे अधिकारी पद पर रहने लायक नहीं हैं। संजय शर्मा ने सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को वाल्मीकि समाज से जोड़ते हुए कहा कि वाल्मीकि समाज उनका अपना समाज है और वे समाज के सुख-दुख में हमेशा साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि समाज के लोगों के साथ कोई समस्या आती है तो वह उनके साथ खड़े रहेंगे। मंत्री ने धरने के दौरान स्पष्ट किया कि जब तक सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाते, तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे। धरने के दौरान वन मंत्री ने अलवर में वकीलों के नए भवन से जुड़े मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में भी जिला प्रशासन की ओर से अड़चनें पैदा गई।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पर निकलेगा मौन जुलूस

कटिहार (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष मनोज राय की अध्यक्षता में आगामी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी, प्रदेश मंत्री सीमा झा, जिला महामंत्री रामनाथ पांडे, सौरभ कुमार मालाकार, जिला उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश चौधरी, अशोक गुप्ता और गौरव पासवान उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि पार्टी के निर्देशों के अनुसार मंडल, शक्ति केंद्र और जिला स्तर की बैठकें महीने में एक बार विभिन्न तिथियों पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि संगठन के कार्यों को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों के संबंध में बताया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, जिसकी पूर्व संध्या पर जिला प्रभारी मंत्री एवं बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी की उपस्थिति में एक भव्य मौन जुलूस निकाला जाएगा। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष ने कहा कि कटिहार जिला मुख्यालय एवं मंडल स्तर पर भव्य रूप से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी तथा 15 अगस्त को भाजपा जिला कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जयंती से जुड़े कार्यक्रमों को शक्ति केंद्र, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक आयोजित करने के लिए विशेष तैयारी करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में आगामी विभिन्न कार्यक्रमों को मंडल स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सफलतापूर्वक संपन्न करने का कार्य करेगी।

बिहार कैबिनेट के 10 प्रस्तावों पर मुहर, ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक हटेगी

पटना (हिंस)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर लगी रोक हटाने समेत कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ऊर्जा, शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी और छात्र कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गयाजी और बिहारशरीफ में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष सचिव संजय कुमार को 31 अगस्त 2026 को सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय उपभोक्ताओं को केंद्रांश के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके तहत 10,000 रुपए प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम 20,000 रुपए प्रति उपभोक्ता की सहायता दी जाएगी। गांवों में भारतनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार, बीबीएनएल और राज्य सरकार के बीच समझौता करने की भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के अधीन ग्रिड उपकेंद्र कार्यालयों और पूर्व निर्धारित यार्ड स्टिक के अनुसार विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और विद्युत अभियंता समेत कुल 221 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने *सात निश्चय-3* के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी। इसके लिए 430.08 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कार्यक्रम के तहत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन, सोलर, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, टेली, विदेशी भाषाओं और उद्यमिता जैसे भविष्य के कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे प्रत्यक्ष रूप से 6,436 रोजगार के अवसर सृजित होने और हर वर्ष 2.57 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिलने का अनुमान है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को भी वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक सुदृढ़ करते हुए अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार देने की मंजूरी दी गई। वर्ष 2026-27 के लिए 950 करोड़ रुपए के व्यय को स्वीकृति दी गई है। सरकार के अनुसार, अब तक 4.81 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और 4.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को करीब 8,865 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बिहार में संचालित एकल निजी शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की नामांकन प्रक्रिया में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

जगतार सिंह हवारा की पैरोल के लिए राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री मान

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा की पैरोल का मामला गरमा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर जगतार सिंह हवारा को मानवीय आधार पर 10 दिन की पैरोल देने के लिए सिफारिश करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 साल बाद उनकी बीमार माता के अपने बेटे से मिलने की उम्मीद फिर से जगी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है, क्योंकि मामले की सुनवाई दिल्ली में चल रही है। उन्होंने साथ ही भरोसा दिलाया कि यदि हवारा को पैरोल दी जाती है, तो पंजाब सरकार कानून-व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जगतार सिंह हवारा पिछले 31 वर्षों से जेल में बंद हैं। उनकी माता वृद्धावस्था में हैं, उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और इस समय अर्ध-बेहोशी की अवस्था में हैं। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए मैंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे जगतार सिंह हवारा को जल्द से

जल्द 10 दिन की पैरोल देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, ताकि वह अपनी माता से मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगतार सिंह हवारा के अपने घर आने के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की राज्य सरकार पूरी गारंटी लेती है। उनके समर्थकों और परिवार के सदस्यों ने भी इस संबंध में राज्य सरकार को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पंजाब में कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

गुरबाणी प्रसारण को लेकर एसजीपीसी और जीटीसी नेटवर्क आमने-सामने, अमृतसर पुलिस में शिकायत दर्ज

चंडीगढ़ (हिंस)। श्री गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित गुरबाणी के लाइव प्रसारण को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जीटीसी नेटवर्क आमने-सामने आ गए हैं। एसजीपीसी ने जीटीसी नेटवर्क के खिलाफ अमृतसर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि नेटवर्क ने श्री हरमंदिर साहिब से गुरबाणी के लाइव प्रसारण से जुड़ी निर्धारित नीति और अधिकारों का उल्लंघन किया है। एसजीपीसी का कहना है कि श्री हरमंदिर साहिब से गुरबाणी के प्रसारण की अनुमति देने या रोकने का कानूनी अधिकार केवल एसजीपीसी के पास है। कमेटी के अनुसार पीटीसी नेटवर्क एसजीपीसी की अनुमति और अधिकृत व्यवस्था के तहत उसके यूट्यूब चैनल पर गुरबाणी के लाइव प्रसारण की तकनीकी व्यवस्था संभालता है। एसजीपीसी का दावा है कि जीटीसी नेटवर्क को इस तरह के प्रसारण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। एसजीपीसी के कानूनी सलाहकार अमनबीर सिंह सियाली ने शिकायत की पुष्टि करते हुए कहा कि एसजीपीसी ने अमृतसर पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कर जीटीसी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसजीपीसी का आरोप है कि जीटीसी नेटवर्क ने 6 अगस्त से एसजीपीसी की अनुमति के बिना अपने लोगो के साथ गुरबाणी का प्रसारण शुरू किया। इसके बाद एसजीपीसी ने नेटवर्क को कानूनी नोटिस भेजा, जिसके चलते कुछ समय के लिए प्रसारण बंद हुआ, लेकिन बाद में इसे दोबारा शुरू कर दिया गया। एसजीपीसी के कानूनी सलाहकार ने कहा कि सोशल मीडिया या यूट्यूब पर एसजीपीसी की लाइव फीड का लिंक शेयर करना अलग बात है और इसे अनुमति दी गई है, लेकिन किसी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर अपने लोगो के साथ गुरबाणी की फीड को दोबारा प्रसारित करना अलग मामला है और इसके लिए एसजीपीसी की अनुमति आवश्यक है। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के अनुसार जीटीसी नेटवर्क ने 5 अगस्त की रात करीब 9 बजे गुरबाणी प्रसारण की अनुमति मांगते हुए पत्र भेजा था। एसजीपीसी का आरोप है कि जवाब का इंतजार किए बिना नेटवर्क ने अगले दिन सुबह एसजीपीसी के यूट्यूब चैनल से लिंक लेकर करीब 3.15 बजे गुरबाणी का दोबारा प्रसारण शुरू कर दिया। दूसरी ओर, जीटीसी नेटवर्क के संस्थापक और प्रबंध निदेशक रवींद्र नारायण ने एसजीपीसी के आरोपों को लेकर कहा कि कमेटी नेटवर्क के खिलाफ *चुनिंदा कार्रवाई* कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कई अन्य चैनल भी एसजीपीसी के अधिकृत चैनल से गुरबाणी की लाइव फीड प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। नारायण ने आरोप लगाया कि कुछ चैनल एसजीपीसी की फीड पर अपने लोगो लगा रहे हैं और कुछ चैनल एसजीपीसी का लोगो भी हटा देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी, तो वह इसके प्रमाण भी उपलब्ध करा सकते हैं। एसजीपीसी फिलहाल अपने *एसजीपीसी श्री अमृतसर* यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिन में तीन बार गुरबाणी का प्रसारण करता है। इसके अलावा फेसबुक, आधिकारिक वेबसाइट और एप्पल एप्लीकेशन के जरिए भी प्रसारण उपलब्ध कराया जाता है। एसजीपीसी ने स्पष्ट किया है कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म गुरबाणी की फीड को री-स्ट्रीम, डाउनलोड या दोबारा प्रसारित नहीं कर सकता।

महिलाओं के आत्म सम्मान में लहरिया महोत्सव 15 को हस्त कलाकारों को प्रोत्साहन के साथ एक नई पहचान देंगे

बीकानेर (हिंस)। सरस फाउंडेशन के नेतृत्व में जानवी नेल्स स्टूडियो की ओर से आगामी 15 अगस्त, शनिवार को महिलाओं के आत्म सम्मान ओं लहरिया महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के प्रचार-प्रसार के लिए बुलाए गए पत्रकारों को फाउंडेशन की चेयरमैन और फोर्ट स्कूल की प्रिंसीपल पिंकी शर्मा ने जानकारी दी। इस अवसर पर प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट और स्टूडियो फाउंडर जानवी सोनी, सनराईज ब्यूटी पार्लर की संचालिका मीनाक्षी किराडू, मोहिनी खत्री सहित अनेक मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मिस लहरिया बीकानेर, मिसेज लहरिया बीकानेर, मॉडलिंग प्रतियोगिता, डांसिंग प्रतियोगिता, नेल आर्ट प्रतियोगिता, मेहन्दी

प्रतियोगिता आयोजित होंगी। वहीं विभिन्न प्रकार की स्टॉल एवं एग्जीबिशन के माध्यम से हस्तकला को बढ़ावा देते हुए हस्त कलाकारों को प्रोत्साहन के साथ एक नई पहचान दी जाएगी। साथ ही साथ महिलाओं के आत्मसम्मान ओं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा।

सर्राफा बाजार में उछला सोना, चांदी ने भी लगाई बड़ी छलांग

नई दिल्ली

सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 1,720 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,870 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चेन्नई में सोने की कीमत 2,020 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,210 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गई है। इसके अलावा सर्राफा बाजार में हाजिर चांदी ने भी 10,200 रुपये प्रति किलोग्राम तक की छलांग लगाई है।

कीमत में हुए इस बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,53,830 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,54,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,41,010 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,41,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी उछाल आने की वजह से ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,55,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,53,980 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,53,830 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,41,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,53,880 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,060 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,54,380 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,41,510 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,53,830 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,41,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,41,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,53,980 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,41,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,41,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,53,980 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,41,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोना शुरुआती कारोबार के दौरान जोरदार उछाल के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,53,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,41,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

न्यूज ब्रीफ

ग्रामीण भारत और छोटे व्यवसायों को एआई से सशक्त करें: एसबीआई चेयरमैन

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को ग्रामीण ग्राहकों, छोटे व्यवसायों और कृषि तक गहरा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। शेट्टी ने स्पष्ट किया कि एआई की वास्तविक परीक्षा उसकी बारीकियों में नहीं, बल्कि उससे हासिल होने वाली उपलब्धियों में है। उन्होंने जोर दिया कि एआई को अर्थव्यवस्था में गहराई तक ले जाना होगा, खासकर ग्रामीण भारत, छोटे कारोबारियों और पारंपरिक ऋण माडल में शामिल न होने वाले ग्राहकों तक। उन्होंने बताया कि एआई कृषि क्षेत्र में जोखिम आकलन, डिजिटल रिकार्ड और सैटेलाइट इमेज के माध्यम से ऋण पहुंच और पोर्टफोलियो प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, शेट्टी ने स्वीकार किया कि कुछ एआई तकनीकों को कृषि ऋण में पहले से अपनाया जा रहा है, लेकिन चुनौती उन्हें पायलट प्रोजेक्ट से आगे ले जाकर अंतिम छोर तक किफायती और व्यावहारिक बनाने की है। उन्होंने आगाह किया कि एआई के बढ़ते उपयोग से साइबर सुरक्षा जैसे नए जोखिम उत्पन्न होंगे, क्योंकि यह हमलावरों को अधिक परिष्कृत खतरे विकसित करने की अनुमति दे सकता है। बैंकों को अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी और विश्वास बनाए रखने के लिए अपने ढांचे पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि एआई सिस्टम अधिक स्वायत्त हो जाएंगे।

यूपीआई लेन-देन पर शुल्क का विवादः उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त रहेगा लेन-देन

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के बीच, वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए एक विधेयक ने यूपीआई और रुपये पे डेबिट कार्ड लेनदेन पर संभावित शुल्क को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इस कदम से सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर अपने डिजिटल भुगतान प्रणाली में बदलाव किए हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए लेनदेन पूरी तरह से मुफ्त रहेगा और इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। दरअसल, अमेरिकी सरकार लंबे समय से भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सिस्टम पर आपत्ति जाहिर करती रही है। अमेरिका ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया है, जो उसकी वीजा और मास्टरकार्ड जैसी बड़ी पेमेंट कंपनियों के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार कर रहे हैं। इस साल मार्च में, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआरी) ने भारत की डिजिटल भुगतान नीतियों को विदेशी व्यापार में बाधा बताया था, उनका कहना था कि ये नीतियां घरेलू कंपनियों को लाभ पहुंचाती हैं।

टाटा कैपिटल का रिवाल्विंग क्रेडिट एक्सपोजर 5 फीसदी से कम, आरबीआई के नए प्रस्ताव से कंपनी पर पड़ेगा सीमित असर

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को रिवाल्विंग क्रेडिट स्कीम बंद करने के प्रस्ताव से टाटा कैपिटल पर नाम मात्र का असर पड़ेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उनके कुल ऋण पोर्टफोलियो में रिवाल्विंग क्रेडिट का हिस्सा 5 फीसदी से भी कम है, जबकि इस कदम से बजाज फाइनेंस जैसी अन्य एनबीएफसी को बड़ी चुनौती मिल सकती है। टाटा कैपिटल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बैंकिंग सम्मेलन में बताया कि वे आरबीआई के इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देंगे और अंतिम विनियमन का पालन करेंगे। रिवाल्विंग क्रेडिट एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जिसमें एक तय सीमा तक बार-बार पैसे उधार लेने और चुकाने की अनुमति होती है। जून के अंत तक टाटा कैपिटल का सकल ऋण 2.86 लाख करोड़ रुपये था। आरबीआई का यह कदम एवरग्रीनिंग के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से है, जहां उधारकर्ता नए ऋण से पुराने ऋण चुकाते हैं। एनबीएफसी की स्व-नियामक संस्था वित्तीय उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) भी इस सप्ताह इस मुद्दे पर चर्चा करेगी।

एसबीआई को वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में 8 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान

मांग, उद्योग और सरकारी खर्च का सहारा, आरबीआई के अनुमान से भी तेज रह सकती है आर्थिक रफ्तार

नई दिल्ली

भारतीय इकोनामी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) की एक नई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर लगभग 8 फीसदी रह सकती है। यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 7 फीसदी के अनुमान से काफी अधिक है, जो मजबूत कारोबार, खरीदारी और व्यापक आर्थिक गतिविधियों की ओर इशारा करता है।

एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि अर्थव्यवस्था की यह मजबूती किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। लोगों की खरीदारी और मांग बनी हुई है, औद्योगिक गतिविधियां अच्छी हैं और सेवा क्षेत्र से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। एसबीआई रिसर्च द्वारा अध्ययन किए गए 54 प्रमुख आर्थिक कारकों में से लगभग 86% में पहली तिमाही के दौरान तेजी देखी गई है, जो पिछले साल की समान अवधि के 69% से काफी अधिक है। यह दर्शाता है कि आर्थिक सुधार सिर्फ एक-दो सेक्टर्स तक सीमित नहीं है। सरकार का विकास परियोजनाओं पर खर्च और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में तेजी भी अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, कई राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर खर्च जारी है, जो कारोबार और रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। 15 जुलाई 2026 तक बैंकों का कर्ज करीब 17.7 फीसदी की दर से बढ़ा है। इसके अलावा, मानसून में सुधार भी इकोनामी के लिए राहत की खबर है। जून में बारिश में 40 फीसदी की कमी के बावजूद, जुलाई और अगस्त में सामान्य से बेहतर बारिश ने कुल कमी को लगभग 12 फीसदी पर ला दिया है। अच्छी बारिश से खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलता है, जिससे किसानों की आय और गांवों में मांग बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्ट ने रुपये की कमजोरी को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। डालर के मुकाबले रुपये का 96 के स्तर को पार कर जाना चिंता का विषय था, हालांकि बाद में इसमें सुधार आया।

अब प्लास्टिक और फ़ाइल में नहीं मिलेगा पान मसाला : एफएसएसएआई

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। अब पान मसाला को प्लास्टिक, एल्युमीनियम फ़ाइल या मेटलाइज्ड लेयर वाले मटीरियल में पैक नहीं किया जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन नियम, 2026 के तहत 10 अगस्त को भारत के राजपत्र में प्रकाशित इन नए प्रावधानों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित पैकेजिंग सुनिश्चित करना है। नए नियमों के अनुसार पान मसाला को अब अनुसूची 4 में एक नई श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है। एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि पान मसाला की पैकेजिंग के लिए कागज, पेपरबोर्ड, सेलुलोज या प्राकृतिक रूप से मिलने वाले अन्य मटीरियल का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते इनमें प्लास्टिक का कोई अंश न हो। इसके तहत पालीइथिलीन, पालीप्रोपाइलीन, पालिएस्टर, पालीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) या कोई अन्य सिंथेटिक पालीमर को-पालीमर या लैमिनेट प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। यहां तक कि कागज की बाहरी परत होने पर भी अंदर प्लास्टिक या मेटलाइज्ड लेयर का उपयोग वर्जित है। विनिर्माताओं के लिए एफएसएसएआई ने टिन या कांच के कंटेनर को भी पैकेजिंग के मंजूर विकल्पों में शामिल किया है। यह संशोधन खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) नियम, 2018 में बदलाव के रूप में आया है। इसके अलावा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के कुछ नियम भी पान मसाला की पैकेजिंग पर लागू होंगे। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। एफएसएसएआई ने इन बदलावों को अंतिम रूप देने से पहले 28 अप्रैल को ड्राफ़्ट जारी कर जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे, जिन पर विचार करने के बाद ही यह अंतिम अधिसूचना जारी की गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि यह नियम पान मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि केवल उनकी पैकेजिंग सामग्री को प्लास्टिक-मुक्त कर पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की ओर ले जाने पर केंद्रित है।

बैंकिंग में एआई का जिम्मेदारी से करें इस्तेमाल आरबीआई गवर्नर

नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। एफआईबीएसी 2026 सम्मेलन को संबोधित करते हुए मल्होत्रा ने साफ कहा कि एआई को नियंत्रित किए जाने वाले जोखिम के बजाय एक क्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए जिसका सावधानी से उपयोग हो। साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में आगाह किया कि बैंक के फैसलों की जिम्मेदारी अंततः बैंक की ही होती है, न कि उसके एल्गोरिद्म की।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देशों के सदस्य तेज भुगतान प्रणाली को केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) से जोड़ने पर भी चर्चा कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने एआई माडल से जुड़े जोखिमों पर बोलते हुए कहा कि आरबीआई इसे क्षमता के रूप में देखता है। हालांकि, उन्होंने चेताया कि बैंकिंग प्रणाली में एआई अपनाने से मानवीय निर्णय क्षमता और जवाबदेही कम होने का जोखिम हो सकता है।

बैंक के फैसलों की जिम्मेदारी अंततः बैंक की ही होती है, न कि उसके एल्गोरिद्म की

मल्होत्रा ने जोर दिया, हम यह नहीं कह सकते कि फैसला माडल ने किया। इसमें सार्थक मानवीय निगरानी, फैसले को समझाने और हस्तक्षेप करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने इसे ब्लैक बाक्स समस्या बताते हुए कहा कि एआई सिस्टम के किसी छोटे व्यवसाय को कर्ज न देने की सलाह देने पर, ऋणदाता और नियामक दोनों को कारण जानने का हक है। मल्होत्रा ने एआई में पक्षपात और भेदभाव के जोखिम पर भी आगाह किया, खासकर अगर वह पुराने कर्ज के आंकड़ों पर आधारित हो। उन्होंने थर्ड-पार्टी वेंडर पर निर्भरता और डेटा गोपनीयता के खतरों का भी जिक्र किया, कहा कि ग्राहकों को डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा कानून के पालन से कहीं ज्यादा की उम्मीद करनी चाहिए। आरबीआई गवर्नर ने भारतीय बैंकों को एआई अपनाने में पीछे न रहने पर जोर देते हुए कहा कि वैकल्पिक डेटा जैसे नकदी प्रवाह और जीएसटी फाइलिंग पर प्रशिक्षित एआई माडल ऋण आवंटन की लागत को कम कर सकते हैं।

बैंकों में 2.31 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के फ्राड, वसूली केवल 2.7 फीसदी

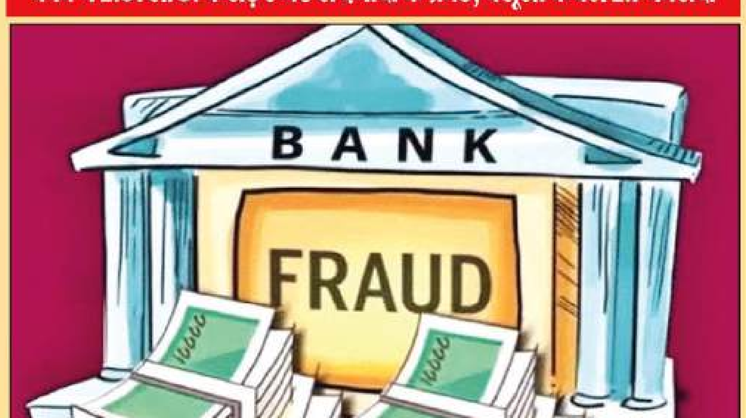

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में बड़े वित्तीय फ्राड की चिंताजनक तस्वीर पेश की है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2026 के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 5,607 धोखाधड़ी मामलों में 2,31,710.12 करोड़ रुपए की रकम शामिल थी, जिसमें से महज 6,283.14 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई। यह दर्शाता है कि 2,25,426.98 करोड़ रुपए की बड़ी राशि अभी भी फंसी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, जहां 2021 से 2024 तक बड़े फ्राड के मामलों और राशि में गिरावट देखी गई, वहीं वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में इनमें तेज उछाल आया। वित्त वर्ष 24 में 641 मामलों के साथ 9,080.50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई, जो छह साल का निचला स्तर था।

सेबी का प्रस्ताव : कमोडिटी डेरिवेटिव में एफपीआई की बढ़ेगी भागीदारी, खुलेंगे नए रास्ते

इन बदलावों से बाजार में तरलता, मूल्य खोज और वैश्विक बाजारों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित होगा

नई दिल्ली

बाजार नियामक सेबी ने एक्सचेंज-ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि इंडेक्स डेरिवेटिव्स और नकदी के बिना सेटल होने वाले गैर-कृषि जिंस डेरिवेटिव्स में एफपीआई को व्यापार की अनुमति देना है। सेबी का मानना है कि इन बदलावों से बाजार में तरलता, मूल्य खोज और वैश्विक बाजारों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित होगा। मंगल को जारी अपने परामर्श पत्र में सेबी ने दो प्रमुख प्रस्ताव रखे हैं।

पहले प्रस्ताव के तहत, एफपीआई को अब गैर-कृषि इंडेक्स डेरिवेटिव अनुबंधों में भाग लेने की अनुमति मिलेगी, भले ही इनकी अंतर्निहित संपत्तियां नकदी में सेटल होती हों या नहीं। वर्तमान में, एफपीआई केवल नकदी में सेटल होने वाले गैर-कृषि डेरिवेटिव अनुबंधों में ही निवेश कर सकते हैं।

चूंकि इंडेक्स डेरिवेटिव्स का निपटान हमेशा नकदी में ही होता है, इसलिए यह बदलाव डिलीवरी से जुड़ी कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी (सीडीएसी) ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। दूसरे प्रस्ताव में एफपीआई को घरेलू एक्सचेंजों पर उपलब्ध फिजिकली सेटल होने वाले गैर-कृषि जिंस डेरिवेटिव्स में भी भागीदारी की इजाजत देने की बात कही गई है।

इनमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, चांदी और आधार धातु जैसे वैश्विक बेंचमार्क से जुड़े जिंस शामिल हैं। सेबी के अनुसार, इससे बाजार में प्रतिभागियों का आधार और तरलता बढ़ेगी, साथ ही भारत का कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार अंतरराष्ट्रीय जिंस बाजार से गहराई से जुड़ सकेगा। हालांकि, एफपीआई को टेंडर अवधि शुरू होने से पहले (एक्सपायरी से तीन दिन पूर्व) अपने निवेश को बेचना या रोल-ओवर करना होगा। ऐसा न कर पाने पर उनकी खुली पोजीशन स्वचालित रूप से किसी ट्रेडिंग मेंबर के खातों में हस्तांतरित हो जाएंगी।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान दबाव में कारोबार करते रहे। डाउ जान्स फ्यूचर्स भी मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। एशियाई बाजार में भी मिला-जुला कारोबार हो रहा है।

अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन (सीपीआई) यानी महंगाई का आंकड़ा जारी होने वाला है। महंगाई का आंकड़ा आने के पहले अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान निवेशक सतर्क मुद्रा में कारोबार करते रहे। डाउ जान्स इंडस्ट्रियल एवरेज दिन के ऊपरी स्तर से 430 अंक लुढ़क कर 180 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ।

इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.32 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 7,728.20 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया।

इसके अलावा नैस्डेक 159.91 अंक यानी 0.60 प्रतिशत टूट कर 26,445.45 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.02 प्रतिशत की सांकेतिक कमजोरी के साथ 53,783.16 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान दबाव में कारोबार करने के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.17 प्रतिशत फिसल कर 10,844.19 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,714.94 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके विपरीत डीएएक्स इंडेक्स 0.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,391.42 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से पांच के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि तीन सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। थाईलैंड के स्टाक एक्सचेंज में छुट्टी होने की वजह से सेट कंपोजिट इंडेक्स में कोई हलचल नहीं हो रही है।

गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 0.03 प्रतिशत की सांकेतिक कमजोरी के साथ 24,508.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.40 प्रतिशत लुढ़क कर 5,731.40 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। हैंग सेंग इंडेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल यह सूचकांक 290.82 अंक यानी 1.15 प्रतिशत टूट कर 25,362 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

दूसरी ओर, निक्केई इंडेक्स 379.78 अंक यानी 0.56 प्रतिशत की मजबूती के साथ 67,350 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह ताइवान वेटेड इंडेक्स 225.49 अंक यानी 0.50 प्रतिशत उछल कर 45,346.21 अंक के स्तर पर आ गया है। कोस्पी इंडेक्स में जोरदार तेजी नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 282.70 अंक यानी 4.27 प्रतिशत की छलांग लगा कर 6,628.23 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,297.59 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.31 प्रतिशत की मजबूती के साथ 3,946.51 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

मान्ट्रियल ओपन : बेन शेल्टन का शानदार प्रदर्शन जारी, बिना सेट गंवाए सेमीफाइनल में पहुंचे

मान्ट्रियल

गत चैंपियन अमेरिका के बेन शेल्टन ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट (मान्ट्रियल ओपन) के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शेल्टन ने क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य के याकुब मेन्सिक को लगातार सेटों में 6-3, 6-1 से हराया।

23 वर्षीय शेल्टन ने इस साल के कनाडाई एटीपी मास्टर्स 1000 में लगातार चौथी जीत दर्ज की और चारों मुकाबलों में एक भी सेट नहीं गंवाया है।

मेन्सिक के खिलाफ शेल्टन ने 18 विनर्स लगाए और सिर्फ तीन अनफोर्स्ड एरर किए। उन्होंने अपनी पहली सर्विस पर 89 प्रतिशत अंक जीते। मुकाबले में उन्हें एक भी ब्रेक प्वाइंट का सामना नहीं करना पड़ा।

शेल्टन ने मैच के दौरान 147 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सर्विस भी की

जीत के बाद शेल्टन ने कहा, यह शानदार लगा। मैं अपनी रिटर्न गेम से बहुत खुश था। ग्राउंड्स से जिस तरह मैंने पहले अंक से खेला, मैं इसी स्तर का प्रदर्शन करना चाहता हूं। पूरे मैच के दौरान मैं जिस स्तर को बनाए रखने में सफल रहा, उससे मैं बेहद खुश हूं। उम्मीद है कि सेमीफाइनल में भी इस प्रदर्शन को आगे बढ़ा पाऊंगा।

लर्नर टीएन से होगी भिड़ंत

मान्ट्रियल टूर्नामेंट के ड्रा में बचे एकमात्र शीर्ष-10 खिलाड़ी शेल्टन का सेमीफाइनल में अमेरिका के 12वीं वरीयता प्राप्त लर्नर टीएन से मुकाबला होगा। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक दो मुकाबले हुए हैं और दोनों में टीएन ने जीत दर्ज की है। इस साल इंडियन वेल्स के दूसरे दौर में भी टीएन ने शेल्टन को हराया था।

टीएन ने क्वार्टर फाइनल में डेनियल मेरिडा को 6-3, 6-2 से हराकर पहली बार मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। 20 वर्षीय टीएन ने यह मुकाबला एक घंटे 12 मिनट में अपने नाम किया।

टीएन ने इस साल आस्ट्रेलियन ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल खेला था। इसके बाद इंडियन वेल्स में पहली बार मास्टर्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और जेनेवा में अपने करियर का पहला क्ले कोर्ट खिताब भी जीता।

शेल्टन के खिलाफ मुकाबले को लेकर टीएन ने कहा, बेन चाहे किसी भी स्थिति में हों, वह अच्छी सर्विस करेंगे। वह बेसलाइन से तेज शाट लगाएंगे। इस समय वह काफी आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं। मैंने उन्हें पहले खेलते हुए देखा और वह बहुत, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

न्यूज ब्रीफ

डीपीएल : सार्थक और वैभव के शानदार अर्धशतकों से नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने दर्ज की शानदार जीत

नई दिल्ली। सार्थक रंजन और वैभव कंडपाल की शानदार पारियों की बदौलत नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 में वेस्ट दिल्ली लायंस को आठ विकेट से हरा दिया। अरुण जेटली स्टेडियम में नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 147 रन का लक्ष्य महज दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। टास के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम नार्थ दिल्ली के गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी के सामने 20 ओवर में 146/7 रन ही बना सकी। लायंस ने शुरुआती विकेट के लिए 36 रन जोड़े, लेकिन अंकित कुमार के 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट होने के बाद टीम का मध्यक्रम लड़खड़ा गया। नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने लगातार विकेट चटकाते हुए वेस्ट दिल्ली का स्कोर 59/5 कर दिया। इसके बाद मयंक गुसाईं और सोमवीर श्योकंद ने छठे विकेट के लिए 68 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर पारी को संभाला। श्योकंद ने 24 गेंदों पर 34 रन बनाए, जबकि गुसाईं 28 गेंदों पर 42 रन बनाकर नाबाद रहे। नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ओर से मयंक डागर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 14 रन देकर दो विकेट हासिल किए। सार्थक और वैभव ने आसान बनाया लक्ष्य 147 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने धमाकेदार शुरुआत की। कप्तान सार्थक रंजन और वैभव कंडपाल ने पहले विकेट के लिए 106 रन की शानदार साझेदारी कर टीम को जीत की राह पर डाल दिया।

कनाडा ओपनः नाओमी ओसाका को हराकर एलेना रायबाकिना सेमीफाइनल में

मान्ट्रियल। दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी कजाखस्तान की एलेना रायबाकिना ने शानदार

वापसी करते हुए जापान की नाओमी ओसाका को तीन सेटों के रोमांचक मुकाबले में 4-6, 7-6 (5), 6-4 से हराकर कनाडा ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। ओसाका ने मुकाबले की शानदार शुरुआत की और रायबाकिना की मैच की पहली ही सर्विस गेम में ब्रेक हासिल कर लिया। अगले गेम में रायबाकिना के पास वापसी का मौका था, लेकिन ओसाका ने तीन ब्रेक प्वाइंट बचाते हुए अपनी सर्विस बरकरार रखी। इसके बाद रायबाकिना पूरे सेट में एक भी ब्रेक प्वाइंट हासिल नहीं कर सकीं और ओसाका ने पहला सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया। रायबाकिना ने दूसरे सेट में अपनी लय हासिल की। हालांकि वह शुरुआती तीन सर्विस गेम में से दो में अपनी सर्विस गंवा बैठीं, लेकिन आस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन ने भी दो बार ओसाका की सर्विस तोड़ी और मुकाबले को टाईब्रेक तक पहुंचाया। रायबाकिना ने टाईब्रेक 7-5 से जीतकर मुकाबला निर्णायक तीसरे सेट में पहुंचा दिया। तीसरे सेट में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। रायबाकिना जब 2-3 से पीछे थीं और उनकी सर्विस पर तीन ब्रेक प्वाइंट थे, तब उन्होंने शानदार धैर्य दिखाया। 27 वर्षीय खिलाड़ी ने कुल चार ब्रेक प्वाइंट बचाकर अपनी सर्विस कायम रखी और मुकाबले की दिशा बदल दी।

इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बीडब्यूएफ विश्व चैम्पिशिप की तैयारियों से उत्साहित हैं सिंधु

नई दिल्ली। यहां 17 से 23 अगस्त तक होने वाले विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप (बीडब्यूएफ) की तैयारियां जोरों

पर हैं। इस चैम्पियनशिप को लेकर स्टार खिलाड़ी पी वी सिंधु भी उत्साहित हैं। सिंधु ने उम्मीद जताई कि इस टूर्नामेंट में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ी भारत की विशेष मेहमाननवाजी का अनुभव भी करेंगे। इस चैम्पियनशिप के लिए नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम को नया रुप दिया जा रहा है। देश में 17 साल बाद ये चैंपियनशिप होगी। इसलिए इस टूर्नामेंट को लेकर प्रशंसकों में भी खासा उत्साह है। हालांकि, इसी स्टेडियम में इस साल जनवरी में इंडिया ओपन के दौरान खिलाड़ियों ने सुविधाओं और परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाए थे। इस बार प्रयास किये जा रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या सामने न आये। यहां तक की बंदरों को दूर रखने के लिए भी पक्के इंतजाम किये जा रहे है। टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला पहले दौर में मौजूदा चैंपियन और टाप सीड चीन के शी यूकी से होगा। यह मुकाबला भारतीय प्रशंसकों के लिए टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक शुरुआती मैचों में से एक हो सकता है।

हर घर तिरंगा रैली में बोले खेल मंत्री, फिटनेस के साथ प्रदूषण और ट्रैफिक का भी समाधान है साइकिल

नई दिल्ली

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डा. मनसुख मांडविया ने दिल्ली में हर घर तिरंगा साइकिल रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना न केवल फिटनेस को बढ़ावा देता है, बल्कि प्रदूषण और यातायात जैसी समस्याओं से निपटने में भी मददगार हो सकता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय से आयोजित इस रैली में 1,000 से अधिक मायभारत स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।

रैली के दौरान पत्रकारों से बातचीत में डा. मांडविया ने कहा, दिल्ली में 1,000 से अधिक मायभारत स्वयंसेवकों ने हर घर तिरंगा साइकिल रैली के माध्यम से देश को फिटनेस का संदेश दिया है। किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि देश के नागरिक स्वस्थ रहें।

उन्होंने साइकिल चलाने के व्यापक लाभों पर जोर देते हुए कहा, साइकिल फिटनेस का संदेश है, साइकिल प्रदूषण का समाधान है और साइकिल यातायात की समस्या का भी समाधान है।

स्वतंत्रता दिवस के आसपास आयोजित कार्यक्रमों के तहत डा. मांडविया ने मायभारत स्वयंसेवकों के साथ हर घर तिरंगा रैली में भी हिस्सा लिया।

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राओं और तिरंगा रैलियों में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की थी। उन्होंने इसे भारत की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बताते हुए विकसित भारत के निर्माण के संकल्प से जोड़ने का आह्वान किया।

अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान हमारे राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। यह हमें विकसित भारत के निर्माण के संकल्प में एकजुट करता है। इस वर्ष यह अभियान वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के अवसर से जुड़ा है, जिससे हर देशभक्त के लिए इसका महत्व और बढ़ गया है।

उन्होंने नागरिकों से तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम् के गायन में भाग लेने के साथ घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने की अपील की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया था।

प्रधानमंत्री ने कहा था कि तिरंगा देश का गौरव और प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा है।

उन्होंने इस वर्ष के अभियान को वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित किए जाने पर भी खुशी जताई थी। 2022 में शुरू हुआ था हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 2022 में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान अब हर स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय परंपरा बन चुका है। इसके तहत करोड़ों नागरिक स्वेच्छा से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।

इस वर्ष अभियान का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के साथ आयोजित किया जा रहा है।

देशभर में हर घर तिरंगा कार्यक्रमों के दौरान वंदे मातरम् का सामूहिक गायन भी प्रमुख हिस्सा होगा।

नागरिकों को राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की सही धुन और प्रस्तुति सीखने में मदद के लिए संस्कृति मंत्रालय ने पांच चरणों वाला आनलाइन ट्यूटोरियल तैयार किया है। यह ट्यूटोरियल समर्पित वेबसाइट और हर घर तिरंगा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

इस वर्ष तिरंगे के साथ सेल्फी लेने की सुविधा में वंदे मातरम् के बोल और उसकी धुन को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हर घर तिरंगा प्रदर्शनियों में राष्ट्रगीत के इतिहास को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

राटरडैम डाकर्स की जर्सी लान्च, जोंटी रोड्स और जान अब्राहम ने किया अनावरण

मुंबई

यूरोप में क्रिकेट को नई पहचान देने की तैयारी कर रही यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) के उद्घाटन सत्र से पहले राटरडैम डाकर्स ने अपनी आधिकारिक जर्सी लान्च कर दी है। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में टीम के सह-मालिक और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स, अभिनेता एवं सह-मालिक जान अब्राहम और फ्रेंचाइजी के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक मधुकर श्री की मौजूदगी में जर्सी का अनावरण किया गया।

इस अवसर पर फ्रेंचाइजी ने फायरफ्लाइज डाट एआई को अपना आधिकारिक जर्सी पार्टनर बनाने की घोषणा भी की। कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ कृष्ण रमीनेनी राटरडैम डाकर्स के फाउंडिंग इन्वेस्टर के रूप में भी टीम से जुड़ गए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य क्रिकेट, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है।

फायरफ्लाइज डाट एआई बनी आधिकारिक जर्सी पार्टनर

जोंटी रोड्स ने कहा कि राटरडैम यूरोप का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है और डाकर्स की कोशिश यूरोप में क्रिकेट के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करने की होगी। उन्होंने खास तौर पर नीदरलैंड्स सहित यूरोप के युवा क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने और सीखने का अवसर देने की बात कही।

जान अब्राहम ने कहा कि ईटीपीएल के जरिए नीदरलैंड्स, आयरलैंड और स्काटलैंड में जमीनी स्तर पर क्रिकेट प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर मिलेगा। उनका मानना है कि इस लीग से क्रिकेट को वैश्विक खेल बनाने की दिशा में मदद मिल सकती है।

राटरडैम डाकर्स ईटीपीएल के उद्घाटन मुकाबले में 26 अगस्त को वूरबर्ग में एम्स्टर्डम फ्लेम्स के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। टीम के सह-मालिकों में जोंटी रोड्स, जान अब्राहम और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस शामिल हैं। डु प्लेसिस टीम की अगुवाई करेंगे।

टीम में हेनरिक क्लासेन, एनरिक नार्खिया, लोगान वैन बीक और रोएलोफ वैन डर मर्वे जैसे अनुभवी टी20 खिलाड़ी भी शामिल हैं। इनके साथ नीदरलैंड्स के उभरते क्रिकेटरों को भी टीम में जगह दी गई है।

रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जार्जीना से शादी रचायी

लिस्बन। पुर्तगाल के कप्तान और स्टार फुटबालर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 11 साल साथ रहने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड जार्जीना रोड्रिगेज से शादी रचायी है। रोनाल्डो और जार्जीना ने अपनी शादी की जानकारी सोशल मीडिया के जरिये दी है। इस रोमांटिक जोड़े ने पुर्तगाल के कासकैस में एक निजी समारोह आयोजित कर शादी की रस्मे निभाई। ठीक एक साल पहले 11 अगस्त 2025 को ही दोनों की सगायी हुई थी। इस यादगार अवसर पर उनके परिवार के करीबी सदस्यों के साथ ही उनके बच्चे भी उपस्थित थे। रोनाल्डो और जार्जीना ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा की हैं, उनमें उनके बाएं हाथ की उंगलियों में अंगूठियां साफ दिखाई दे रही हैं। इस समारोह की कोई अन्य तस्वीर या वीडियो अब तक सामने नहीं आये हैं। इस दंपत्ति के शादी से पहले ही पांच बच्चे हुए हैं। इनके नाम क्रिस्टियानो जूनियर, जुड़वां बच्चे ईवा और माटेओ, अलाना मार्टिना और बेला एस्मेरल्डा आदि हैं। रोनाल्डो खेल के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के ही साथ समय बिताते हैं। जब भी उन्हें खेल से फुर्सत मिलती है, वह अधिकतर उनके साथ ही छुट्टियां बिताने जाते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते हैं। यह जोड़ा सोशल मीडिया पर भी परिवार से जुड़ी जानकारी साझा करते है।

औरैया के लाल आर्यन सिंह राजावत ने नेपाल में जीता गोल्ड

अब थाईलैंड में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व, 27 से 31 अगस्त तक बैंकाक में होगी चैंपियनशिप

औरैया

उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के अजीतमल क्षेत्र के ग्राम मुड़ैना रूपशाह निवासी 15 वर्षीय युवा फुटबाल खिलाड़ी आर्यन सिंह राजावत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। नेपाल में आयोजित इंडो-नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप-2082 की अंडर-18 फुटबाल प्रतियोगिता में आर्यन ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

आर्यन, अजीत सिंह राजावत एवं अंजू सिंह के पुत्र हैं। नेपाल में शानदार प्रदर्शन के बाद अब उनका चयन थाईलैंड चैंपियनशिप-2026 के लिए हुआ है। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में आर्यन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चैंपियनशिप का आयोजन 27 से 31 अगस्त 2026 तक बैंकाक में किया जाएगा। आर्यन अब भारत की जर्सी में मैदान पर उतरकर देश के लिए पदक जीतने के लक्ष्य के साथ तैयारी में जुटे हैं।

आर्यन की इस सफलता में उनके प्रशिक्षक राकेश सरसैया के मार्गदर्शन के साथ मां कंकेश्वरी स्पोर्ट्स, इंदौर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवार की ओर से उनकी बहन वांशिका लगातार उनका उत्साह बढ़ा रही हैं। परिजनों का सहयोग और प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन आर्यन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर रहा है।

नेपाल में गोल्ड मेडल जीतने के बाद आर्यन के थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करने की खबर से परिवार, गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने आर्यन की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की है।

नेपाल में गोल्ड के बाद अब बैंकाक में तिरंगा लहराने की तैयारी है। आर्यन की उपलब्धि न केवल औरैया बल्कि क्षेत्र के उन युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बनी है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने का सपना देख रहे हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए आस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन घोषित, हेजलवुड की वापसी

डार्विन

आस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 13 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है। अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की टीम में वापसी हुई है, जबकि स्काट बोलैंड को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली। इसके साथ ही आस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी की तिकड़ी पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और हेजलवुड एक बार फिर साथ नजर आएगी।

आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टेस्ट की पूर्व संध्या पर पुष्टि की कि बोलैंड पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे। हेजलवुड करीब आठ महीने बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन भी टीम में लौटे हैं। हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वह एशेज के अंतिम चरण में नहीं खेल पाए थे। आलराउंडर कैमरन ग्रीन ने अपनी जगह बरकरार रखी है और उनके साथ ब्यू वेबस्टर भी टीम में शामिल हैं।

आस्ट्रेलिया ने लगातार दो तेज गेंदबाजी आलराउंडरों के साथ उतरने का फैसला किया है।

बोलैंड ने पिछली गर्मियों में एशेज श्रृंखला के सभी पांच टेस्ट खेले थे। उस दौरान कमिंस, हेजलवुड और लियोन के अलग-अलग समय पर उपलब्ध नहीं रहने के कारण उन्होंने आस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि, आने वाले व्यस्त कार्यक्रम में बोलैंड आस्ट्रेलिया की योजनाओं का अहम हिस्सा बने रहेंगे। अगले 12 महीनों में आस्ट्रेलिया के 21 टेस्ट तक खेलने की संभावना है।

आस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 13 से 17 अगस्त तक डार्विन के मरारा स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 22 से 26 अगस्त तक मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में होगा। यह श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र का हिस्सा है। अंक तालिका में आस्ट्रेलिया दूसरे और बांग्लादेश चौथे स्थान पर है।

आस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

जेक वेदराल्ड, ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, ब्यू वेबस्टर, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस (कप्तान), नाथन लियोन और जोश हेजलवुड।

बांग्लादेश की टीम

नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान) , मेहदी हसन मिराज (उपकप्तान), सौम्य सरकार, शादमान इस्लाम, तंजिद हसन तमीम, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, अमीट हसन, जाकेर अली, तैजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, सैयद खालिद अहमद, एबादत हुसैन चौधरी और मुशफिक हसन।

खुद-ब-खुद चलेगा स्मार्ट सूटकेस...

सफर के दौरान भारी-भरकम सूटकेस लोगों को थका देता हो, तो इस स्मार्ट सूटकेस का इस्तेमाल करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस सूटकेस को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक इशारे पर यह आपके साथ-साथ चलेगा। इस अनोखे सूटकेस का निर्माण इजरायल के एनयूए रोबोटिक्स वैज्ञानिकों ने किया है। एनयूए रोबोटिक्स संस्थान के मुताबिक, इस सूटकेस में कैमरा, सेंसर और ब्लूटूथ लगा है। यह यूजर्स के स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर उसके निर्देशों का पालन भी करता है। यह ही नहीं, यह सूटकेस इतना स्मार्ट है कि इसे अगर किसी अनजान शख्स ने टच किया तो इसका अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसमें खास अलार्म किसी के छीनने या चोरी करने की स्थिति में भी जोर-जोर से बजने लगता है। इस सूटकेस को लेकर सफर कर रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल या टैबलेट डिस्चार्ज होने की भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें यूएसबी सॉकेट फिट किया गया है। इसके जरिए आराम से गैजेट्स चार्ज किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें फिट सभी तकनीक सिर्फ 1.5 किलो की हैं जिसे यात्री आसानी से उठा सकते हैं। फिलहाल यह सूटकेस प्लेन सर्फेस पर ही चल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे सीढ़ियों और दूसरी जगह भी चलने लायक बनाया जाना चाहिए। एनयूए रोबोटिक्स संस्थान का कहना है कि अभी इस पर शोध जारी है, वह इसमें नए फीचर जोड़कर इसे और भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक साल के भीतर यह अनोखा सूटकेस लोगों के बीच पहुंच जाएगा।

सख्त त्वचा को ऐसे बनाएं सॉफ्ट...

शेविंग करने में पुरुषों के लिए सहायक होता है स्क्रब। शेविंग करते रहने से पुरुषों के चेहरे की त्वचा कठोर हो जाती है। ऐसे में स्क्रब त्वचा से मृत त्वचा को हटाने का काम करता है, त्वचा की नमी और मुलायमता को बनाए रखता है। इसलिए शेव करने से पहले नींबू का रस या शेविंग जेल लगाएं। इससे शेव आसानी से बन जाती है, त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं और त्वचा संबंधित बीमारी भी नहीं होती है। एक विशेषज्ञ का कहना है कि अच्छी तरह से चेहरे की सफाई करना आवश्यक है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि फोम का ज्यादा इस्तेमाल त्वचा को नुकसान पहुंचाता है।

जीन्स की चेन पर वायकेके क्यों?

क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जीन्स की चेन पर वायकेके क्यों लिखा होता है। हम बताते हैं आपको इसके पीछे का राज। दरअसल वायकेके का फुलफॉर्म योशिदा को-ग्यो-कबुशिकिगऍशिया है। यह दुनिया की सबसे पहली जिप निर्माता कंपनी है। इस कंपनी ने लगभग आधे से ज्यादा जिप बनाई हैं। यह कंपनी 71 देशों में मौजूद है। 1934 में टोक्यो के एक व्यापारी तादाओ योशिदा ने इसका आविष्कार किया था। किसी बड़ी खोज पर ध्यान न देते हुए यह छोटी-सी खोज लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है। चेन के अलावा वायकेके कपड़ों और बैग में लगने वाले और भी उत्पाद बनाती है। इस कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट जॉर्जिया यूएसए में है, जहां हर रोज 70 लाख जिप बनती हैं।

चीटिंग का एक्सपर्ट...

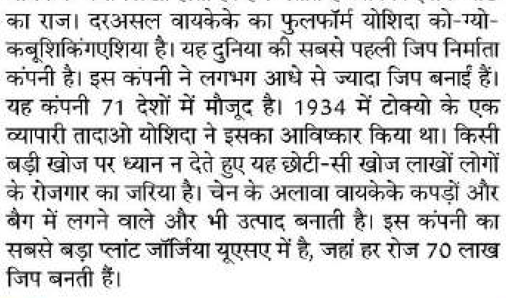

जस्टिन रोस ली नाम का शख्स घूमने और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जाना जाता है लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि न्यूयार्क में रहने वाले इस आदमी को सारी लग्जरियस सुविधाएं फ्री में मिल ही जाती हैं। इसके लिए यह अनोखे तरीके अपनाता है। कभी यह फ्लाइट के खाने को एलर्जिक बताता है तो कभी होटल के इंटरनेट कनेक्शन को गलत बताता है। इससे डिस्काउंट मिलने के साथ ही फ्री सर्विस मिल जाती है। यह अपनी लग्जरियस लाइफ की फोटोज इंस्टाग्राम पर रेग्युलर शेयर करता है। रोस ली चीटिंग में एक्सपर्ट है और यह फ्री अपग्रेड पाने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। अब तक वह शंघाई, मुंबई और टोक्यो में लग्जरियस सुइट में रूकना और फर्स्ट क्लास में सफर करने का फ्री तरीका निकाल चुका है।वह फेक बिजनेस कार्ड बनवाकर डिस्काउंट भी लेता है कुछ दिन पहले एक वीडियो के लीक होने से ली खबरों में आ गया था जिसमें वह ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लूप होल्स और अपने कॉन्ट्रोवर्शियल सीक्रेट बता रहा था। ली कहता है कि मैं इसे क्राइम नहीं मानता। मैं लॉ को फॉलो करता हूं लेकिन अपने रूल खुद बनाता हूं। ली ट्रैवल एक्सपर्ट है और उसकी एक कंपनी भी है।

सुंदर व स्टाइलिश दिखने पर सिर्फ युवतियों का ही कॉपी राइट नहीं है, युवा लड़के भी सुंदर और स्टाइलिश लग सकते हैं। असल में स्टाइलिश मैन बनने के लिए आपको अपनी बॉडी शेप के अनुसार कपड़े पहनने की जरूरत होती है। यह जान लेना चाहिए कि बॉडी पर क्या सूट करता है।

कैसे बनें स्टाइलिश मैन...?

18 से 25 साल के युवा पर्सनल केयर और और स्मार्ट लुक के लिए महिलाओं से अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। और इस बात का ही प्रमाण है कि पिछले पांच साल में युवाओं के प्रयोग में आने वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री का बाजार 42 फीसदी बढ़ गया है। यह सच है कि पहचान बनाने के लिए काम के साथ-साथ आपका पहनावा भी काफी मायने रखता है। ड्रेसिंग स्टाइल में जरा-सी लापरवाही आपकी पर्सनालिटी को बिगाड़ सकती है। फैशन के जानकारों के मुताबिक भारतीय युवाओं को परिधानों के मामले में मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, फैशन के नियम युवाओं के लिए रहस्यमय रहे हैं लेकिन वाकई ये कारगर हैं। आप कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन जब तक आपको इन्हें पहनने के नियम नहीं पता तब तक आप स्टाइलिश मैन नहीं बन सकते। जब बात ड्रेसिंग की हो तो आपके मन में बस लेटेस्ट फंड ही नहीं होना चाहिए। असल में स्टाइलिश मैन बनने के लिए आपको अपनी बॉडी शेप के अनुसार कपड़े पहनने की जरूरत होती है। आपको यह जान लेना चाहिए कि बॉडी पर क्या सूट करता है। अगर आप यहां बताए गए शेप्स में से किसी शेप के हैं तो फिर उन कपड़ों को चुनें जो आप पर फबते हैं।

इनवर्टेड ट्रायंगल

इनवर्टेड ट्रायंगल बॉडी वाले युवाओं का ऊपरी भाग चौड़े चेस्ट और कन्धों के साथ ट्रापेजोइड की तरह होता है लेकिन कूल्हे और कमर इनकी तुलना में नैरो होते हैं। इसलिए ऊपरी भाग निचले भाग से थोड़ा चौड़ा होता है। ऐसी बॉडी टाइप उन युवाओं की होती है जिनकी बॉडी एथलेटिक फ्रेम वाली होती है या जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इस बॉडी स्ट्रक्चर वाले पुरुष हिप एरिया को पॉकेट्स और बेल्ट्स से डिटेलिंग दे सकते हैं। साथ ही वी नैक टी शर्ट्स भी अच्छा ऑप्शन हैं, क्योंकि इससे ध्यान नीचे की तरफ जाएगा। ट्रॉऊजर्स में स्लिम कट और स्ट्रैट फिट बेस्ट होते हैं। ध्यान रहे आपको लोगों का ध्यान शरीर के ऊपरी भाग से हटाना होता है, तो कॉलर के साथ स्ट्रक्चर जैकेट्स और स्कूपिंग नैकलाइन वाले टॉप्स न पहनें।

रेक्टेंगल शेप्स

रेक्टेंगल शेप्स बॉडी टाइप उन युवाओं की होती है जिनके कंधे कमर के बराबर चौड़े होते हैं। तो जब आपको ड्रेसअप होना हो तो मकसद कंधों को चौड़ा और कमर और हिप्स को थोड़ा नैरो दिखाना होना चाहिए। यह शारीरिक तौर पर तो संभव नहीं है लेकिन कुछ कट्स और टाइप्स की वजह से आप यह कर सकते हैं। आप ऐसे जैकेट्स पहन सकते हैं जो कंधों से पैडेड हो और अंडरआर्म से नैरो हों। दूसरा विकल्प है कि समझदारी से लेयरिंग की जाए। औपको डबल ब्रेस्टेड पीसेज जो आपके रेक्टंगुलर शेप को और उभारेगा तो इनसे दूर रहना है।

ओवल शेप

ओवल शेप के युवाओं के शोल्डर नैरो, मध्य ओवल और लोअर लेग स्लिम होते हैं। इस श्रेणी में आने वाले युवाओं को अपने टोरसो को लंबा दिखाकर खुद को स्लिम लुक देना चाहिए। साथ ही कंधों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। डेफिनेशन को ऐड करने के लिए वर्टीकल स्ट्राइप्स या पिन स्ट्राइप्स का चुनाव करें, जिनसे बॉडी को लेंथ मिलती है। गहरे रंग के टेक्सचर लें और फिट लेकिन लूज टेपरड ट्रॉउजर का चुनाव करें ताकी टांगें लंबी दिख सकें। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स और स्टेटमेंट या कलर्ड बेल्ट्स को छोड़ें क्योंकि यह सबका ध्यान कमर की ओर खींचता है जो बॉडी का वाइडेस्ट प्वाइंट है।

ये नियम हैं काम के

फैशन में टाई की नोंक शर्ट के आखिरी बटन को ढंकती हुई होना चाहिए नाकि बेल्ट के नीचे। बेल्ट से नीचे टाई की नोंक का होना एक बहुत बड़ी गलती की तरह बहुत भद्दी दिखती है। जब भी घर से निकलें तो ध्यान रहे कि आपकी कॉलर पर सिलवटें न आ रही हों। कॉलर की सिलवटें आपके व्यक्तित्व पर बुरा असर डालती हैं। जीन्स के साथ पहनने के लिए आपके पास हमेशा अलग से ब्लेजर होना चाहिए। यह देखने में ज्यादा स्टाइलिश लगता है। अगर आप दाढ़ी रखने के शौकीन हैं या फिर आपने फ्रेंच दाढ़ी रखी हुई है, तो भी नियमित अंतराल पर इसकी सेटिंग करवाते रहें। जब भी आप घर से कहीं बाहर जाएं, तो अपने कानों के पीछे और दोनों कलाई पर परफ्यूम का स्प्रे जरूर छिड़के। परफ्यूम लगाने का एक तरीका होता है। इसके लिए सबसे पहले आपने हाथों को सीधा करें इसके बाद अपनी चेस्ट पर परफ्यूम छिड़कें। इस तरह से परफ्यूम लगाने से इसकी खूशबू लंबे समय तक बनी रहती है। यह भी ध्यान रखें कि अच्छा दिखने में आपकी बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज सुस्त है तो सब बेकार। हमेशा कमर को सीधा और छाती को थोड़ा बाहर निकालकर चलें। कंधों को कभी झुकाकर न चलें और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखें। इससे आपकी पर्सनालिटी हमेशा आकर्षक लगेगी।

बॉडी मेकअप

वास्तव में तो लड़कियों से ज्यादा बॉडी मेकअप की जरुरत लड़कों को होती है। शरीर की त्वचा और लुक को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको भी स्पा, बॉडी मसाज, मेनीक्योर और पैडीक्योर करना चाहिए।

ट्रेंडी ब्रेसलेट

ट्रेंडी ब्रेसलेट पूरी दुनिया में युवाओं के बीच मशहूर हैं। स्टाइलिश युवाओं के लिए बहुत सारी एक्सेसरीज मार्केट में उपलब्ध भी है। लैदर कफ से लेकर वुडेन बीड्स तक युवाओं के लिए बहुत से विकल्प हैं, जिनमें से वे अपनी पसंद के ब्रेसलेट चुन सकते हैं। मेटल ब्रेसलेट, नौटिकल ब्रेसलेट तथा बीडेड ब्रेसलेट्स कुछ अच्छे विकल्प हैं।

हेयर ट्रीटमेंट

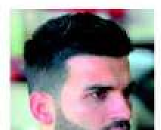

आपका हेयरकट परफेक्ट दिखें इसके लिए जरूरी है कि बालों का भी खास खयाल रखा जाए। खासतौर पर डैंड्रफ और बाल झड़ने जैसी समस्याओं को सुलझा लें। बालों को ऑयल मसाज, हेयर स्पा और रेगुलर कट दें। अगर आप दाढ़ी रखने के शौकीन हैं या फिर आपने फ्रेंच दाढ़ी रखी हुई है, तो भी नियमित समय पर इसकी सेटिंग करवाते रहें।

शू कलेक्शन

कहते हैं की किसी इंसान को उसके जूतों से पहचाना जा सकता है। आपके जूते आपको भीड़ से अलग दिखने में बहुत मदद करते हैं। अगर आप बिना पॉलिश के घिस चुके जूते जो आपके पहनावे से भी मैच नहीं करते, पहन कर कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोई आपके ड्रेस की तारीफ नहीं करेगा, चाहे आपके कपड़े कितने भी अच्छे क्यों न हो। जूतों का सलेक्शन इवेंट के हिसाब से करें। अपने स्टाइल को हमेशा अच्छे शू कलेक्शन से अपग्रेड करते करें। इसके लिए आप ब्राउन या ब्लैक कलर की ड्रेस को ध्यान में रखते हुए शूज खरीद सकते हैं, जो किसी भी स्टाइल से आसानी से मैच हो जाते हैं। अगर आप कॉलेज ब्वाय हैं तो आप लोफर का चयन कर सकते हैं, वो जीन्स और ट्राउजर किसी के साथ भी काफी फबते हैं।

सिंप्लिफाइ योर लुक

जितना हो सके अपने लुक को सिंपल और एलिगेंट रखें। क्योंकि ज्यादा एक्सेसरीज आपको किसी रॉकस्टार या किसी बैंड वाले का लुक दे सकती हैं। तो अगर आप एक्सेसरी पहने के बारे में सोच भी रहे है तो कोशिश करें कि वह ज्यादा न हो और आपकी ड्रेस को ओवरपॉवर न करे।

फिटिंग का रखें ध्यान

ध्यान रखें कि जो भी आप पहनें वह आपके साइज का हो। खुले कपड़े पहनना आपको और मोटा दिखा सकता है। तो ऐसे स्लिम फिट शर्ट, सूट और टीशर्ट से परहेज नकरें। फिट कपड़े पहनें और अपने आप को फिट करने की कोशिश करें।

ब्रैंड पर ध्यान न दें

कपड़े लेते वक्त हर समय ब्रैंड पर ध्यान न दें। क्योंकि कई बार ब्रैंड्स में आपको अच्छे फैब्रिक नहीं मिलते। ऐसे में किसी शर्ट या ट्राउजर के लिए 5000 या 6000 रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है हमेशा एक तरह के लुक में ना रहें। समय-समय पर अपने हेयर स्टाइल या ड्रेसिंग सेंस में बदलाव लाकर लुक को बदलने की कोशिश करें।

छोटी-छोटी चीजें

कई बार छोटे-छोटे स्कार्फ, ब्रेसलेट या पेंडेंट भी आपके लुक को और स्मार्ट बना देते हैं। ऐसे में इन चीजों को खरीदने के बारे में भी सोचें। क्योंकि वॉर्डरोब में हों तो कभी-कभी बड़े काम की होती हैं ये चीजें।

मौके का ध्यान रखें

कपड़ों का चुनाव हमेशा मौके के हिसाब से करें। कहीं जाने से पहले वॉर्डरोब खोलें और कपड़े निकालने से पहले सोचें कि आप इन कपड़ों को पहनकर कहां जाने वाले हैं। फैशन और लेटेस्ट स्टाइल टिप्स से अपडेटेड रहने के लिए फैशन मैग्जीन जरूर पढ़ें। मैग्जीन में आपको हर तरह के स्टाइल कैलेंडर से अपडेट करती है। इनसे आपको बड़े डिजाइनर्स और मॉडल्स के अनुभव के बारे में भी पता चलता है।

समय लें

कुछ भी पहनने से पहले टाइम लें और सोचें। हमेशा लड़कियां ही कपड़ें सलेक्ट करने में टाइम लेने के चलते बदनाम रहती हैं लेकिन यह आदत सही है। आप भी कपड़े पहनने से पहले सोचें और फिर कोई फैसला लें। तैयार होने के बाद अपने दोस्तों से फीडबैक जरूर लें। लेकिन ध्यान रहे कि आप केवल उन्हीं से पूछें जो आपको सही सलाह दें। कई बार दूसरों की राय लेकर भी हमें अपने में सुधार करने का मौका मिलता है।

उम्र के तीसवें पड़ाव से पहले...

हम सभी जीवन में कुछ चीजें तय करते हैं, और हम सभी की एक विश लिस्ट भी होती है जिसमें हम तय करते हैं कि हमें क्या क्या करना है , पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको करनी ही चाहिए चाहे विश लिस्ट में हो या नहीं ! और ये जरूरी नहीं कि यह टू डू लिस्ट जिंदगी भर के लिए हो, ऐज फैक्टर भी होना जरूरी है, आज हम आपको ऐसी ही बातों को बता रहे हैं जो आपको तीस साल की उम्र से पहले जरूर कर लेनी चाहिए।

एक विदेशी भाषा सीखें

आप इस पड़ाव से पहले कम से कम एक विदेशी भाषा जरूर सीखें, यह अंग्रेजी से अलग होनी चाहिए, इससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग तरह का फैलाव आता है।

अकेले यात्राएं करें

इस उम्र तक आते आते आपको यह जरूर सीखना पड़ेगा कि बिना हमसफर के सफर कैसे करें। लंबी यात्राएं काफी उबाऊ होती हैं, और उस पर भी आप अकेले गए तो आपको खुद के साथ बिताने के लिए एक लंबा समय मिलता है, जो कि आपके जीवन के लिए काफी कुछ नया ला सकता है।

एक लंबी रोड ट्रिप करें

उम्र के तीसवें पड़ाव से पहले आपको एक लंबी दूरी की रोड ट्रिप जरूर आजमानी चाहिए। यह एक युवा का एडवेंचर होता है, इसके बाद तो बस तीर्थ यात्राएं रह जाती हैं।

रियल पर्सनालिटी

अब यह समय है कि आप अपनी स्टाइल को अपना लें, अभी तक हम सब पहनावे में प्रयोग करते आ रहे हैं, मगर अब जरूरी है किसी एक लुक को अपनी पहचान बनाने का। तो वह पहने जो आपकी रियल पर्सनालिटी हो, न कि वो जो कि दूसरों जैसा दिखने के लिए हो।

अपनी जड़ों को पहचानें

हम सबके लिए अपने अतीत और अपनी जीवन पद्धति को अपनाना जरुरी है, अब तक की उम्र हमें यह छूट देती थी कि या तो हम किसी भी जीवन शैली में ढालें या बदल जाएं, मगर अब जिम्मेदार होकर एक रास्ता चुनना आवश्यक है।

एक बार मैराथन जरूर दौड़े

यूं तो मैराथन में बच्चे बूढ़े सभी हिस्सा लेते हैं। मगर जो जीतने के लिए दौड़ते हैं वे युवा होते हैं, इसलिए तीस का होने से पहले एक बार मैराथन जीतने के लिए जरूर दौड़े।

खाना खुद बनाना सीखें

यह एक जरुरी काम है, आप हमेशा अपने पार्टनर पर निर्भर न रहें। हर इंसान को अपना खाना खुद बनाना आना चाहिए अब आप किशोर और लड़के नहीं रहे अब आप वयस्क हो रहे हैं तो यह आपको सीखना चाहिए।

बचत करना सीखें

जीवन में आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए बचत करना सीखना ही होगा, और यह आपको 30 का होने से पहले शुरू करना होगा। आखिर में सबसे जरूरी बात इस उम्र से पहले आपको अपनी सभी इन्द्रियों और स्वयं की गारंटी लेनी होगी क्योंकि अब जो गलतियां होंगी उन्हें समाज अपराध ही मानेगा इसलिए मन को नियंत्रण में कर जिम्मेदार बनें।

वेडिंग सीजन का लेटेस्ट ब्राइडल फैशन

क्लासी लुक के साथ ही पाएं परंपरागत डिजाइन

इन दिनों शादियों का दौर चल रहा है। वेडिंग सीजन में पुराने अम्ब्रेला कट घाघरा व चोली बिलकुल आउट है। उनकी जगह ले ली है नए वेडिंग लुक ने। इन दिनों लहंगों की जगह ले ली है स्लीम लांग स्कर्ट्स ने, जिन्हें फिगर हगिंग लॉन्ग स्लीव्स ब्लाउजेस के साथ मैच किया जा रहा है, वहीं इसी के साथ ब्राइडल विअर में ड्रेपिंग भी इन है व इस वजह से साड़ी को लहंगों के साथ भी मिक्स एंड मैच किया जा रहा है। साड़ी गाउन भी काफी चलन में है। अगर आप भी भावी दुल्हन के लिए पोशाक चुनने बाजार का रुख कर रहे हैं तो जरा इन बातों पर भी ध्यान दे दीजिए। कह सकते हैं कि 21 सेंच्यूरी की ब्राइड्स का लुक अब इंटरनेशनल लुक व फील लिए हुए है और वेस्टर्न फैशन से भी काफी हद तक प्रभावित है। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या फैशन में है क्या नहीं।

नेट, वेलवेट भी फेवरेट लिस्ट में शामिल

लहंगों के फेब्रिक की बात करें तो उसमें भी ब्राइड्स की चॉइस केवल सिल्क तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि नेट, वेलवेट भी ब्राइड्स की फेवरेट लिस्ट में शामिल है। ब्लॉक प्रिंट, एम्ब्राइडरी आदि के साथ विभिन्न फेब्रिक्स और पैटर्न्स के साथ मिक्स एंड मैच करे हुए लहंगे चुनने में भी ब्राइड्स बिलकुल नहीं हिचकिचा रही। डिजाइनर साड़ियों की बात करें तो इनमें भी ज्यादा ध्यान ऑर्नेट ब्लाउजेस पर दिया जा रहा है। साड़ी हो या लहंगा, इनकी चोलियों की डिजाइनिंग को खास तवज्जो दी जा रही है। चोलियों की स्वील्स, बेक, फ्रंट, नेक सभी की डिटेलिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कुछ समय पहले तक जहां स्लीव्स को केप स्लीव्स रखा जाता था, वहीं अब इन्हें शॉर्ट, थ्री-क्वार्टर से लेकर लांग तक रखा जा रहा है।

जापानीज क्रेंस है चलन में

जो लोग थोड़ा हैवी लुक पसंद करते हैं वे चमक-दमक वाले विक्टोरियन गाउंस चुन सकते हैं। इन दिनों कारीगरी में जापानीज क्रेंस और चैरी ब्लॉसम्स बहुत चलन में है, जो लहंगे में चार-चांद लगा रहे हैं। इसके साथ थीम को मैच करते किमोनो स्टाइल के ब्लाउज भी खास चलन में हैं। ब्राइडल आउटफिट्स में होने वाली एम्ब्राइडरी अब थीम से इंस्पायर्ड हो गई है। परशियन कारपेट्स, रोज, क्रिस्टल्स, चैरी ब्लॉसम्स जैसी थीम्स बहुत 'इन' है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**